RNI No : JHAHIN/2021/83133

वर्ष- चार, अंक-02, मई- 2024 मूल्यः 20

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

नवजीवन संदेश

जनता किसके साथ

5 महिला समेत 20 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक उग्रवाद प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुआ है। सुकमा में गत दिनों पांच महिला कैडरों समेत कुल 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि सभी नक्सली अमानवीय और खोखली माओवादी विचारधारा से निराश होकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी कथित तौर पर जिले के जगरगुंडा पुलिस थाना क्षेत्र में पोस्टर लगाने, प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा फैलाने और रेकी करने सहित कई माओवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में जिला पुलिस इकाई और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आत्मसमर्पण करने वाले सभी उग्रवादी जिला पुलिस के नक्सलियों के पुनर्वास अभियान नीति से प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

नौ नक्सली को किया गया गिरफ्तार : मालूम हो कि दंतेवाड़ा के भांसी में निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग लगाने वाले नौ नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पांच दिसंबर को डीआरजी, बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा, सीआरपीएफ 111वीं बटालियन एफ कंपनी फरसपाल व थाना फरसपाल का संयुक्त बल सर्चिंग पर निकला था।

कोयला आयात 7.7% बढ़कर 26.82 करोड़ टन पर पहुंचा

समुद्री मार्ग से ढुलाई की कीमतें घटने और गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना के चलते बीते वित्त वर्ष (2023-24) में भारत का कोयला आयात 7.7 प्रतिशत बढ़कर 26.82 करोड़ टन पर पहुंच गया है। बी2बी ई-कॉमर्स कंपनी एमजंक्शन सर्विसेज के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

इससे पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 24.90 करोड़ टन कोयला का आयात था। मार्च, 2024 में भी भारत का कोयला आयात बढ़ा है। यह पिछले साल के समान महीने के 2.11 करोड़ टन से बढ़कर 2.39 करोड़ टन पर पहुंच गया है। मार्च में आयातित कुल कोयले में गैर-कोकिंग कोयले का आयात 1.53 करोड़ टन रहा, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष के समान महीने में यह 1.38 करोड़ टन था। मार्च में कोकिंग कोयले का आयात 53.4 लाख टन रहा, जो इससे पिछले साल के समान महीने में 39.6 लाख टन था। बीते वित्त वर्ष में गैर-कोकिंग कोयले का आयात 17.59 करोड़ टन रहा, जो 2022-23 में 16.24 करोड़ टन था। कोकिंग कोयले का आयात 2023-24 में 5.72 करोड़ टन रहा, जबकि 2022-23 में 5.44 करोड़ टन रहा था।

एमजंक्शन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनय वर्मा ने कहा, ''समुद्री मार्ग से ढुलाई की कीमतों में नरमी और गर्मियों के सीजन में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना से देश का कोयला आयात बढ़ा है। हालांकि, घरेलू बाजार में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए यह देखने वाली बात होगी कि आगामी महीनों में कोयले का आयात मजबूत रहता है या नहीं।''

दीपका खदान में उतरे सीएमडी, मानसून तैयारियों का लिया जायजा

गत दिनों एसईसीएल सीएमडी डॉ प्रेम सागर मिश्रा दीपका मेगा परियोजना के दौरे पर पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने खदान के हर पैच में उत्पादन एवं उत्पादकता से जुड़े विषयों पर चर्चा की एवं आगामी महीनों के लिए उत्पादन योजना के बारे में जानकारी ली। आगामी मानसून को देखते हुए उन्होंने उससे जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने क्षेत्र के सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की साथ ही उत्खनन विभाग के अधिकारियों के साथ डिपार्टमेंटल क्षमता की बेहतर उपयोगिता को लेकर चर्चा की। दौरे के दौरान क्षेत्रीय महाप्रबंधक अमित सक्सेना सर के साथ रहे।

RNI No: JHAHIN/2021/83133

नवजीवन संदेश

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

Web : navjeewansandesh.com

संबद्धता : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (भाषा)

▪ वर्ष -4, ▪ अंक -02, ▪ कुल पृष्ठ -36

index

प्रधान संपादक

पंकज कुमार सिंह

संपादक

प्रभात मजुमदार

संपादक मंडल

जगन्नाथ मुंडा

सुनीता सिन्हा

श्रीमती छाया

रविप्रकाश

खेल डेस्क प्रभारी

चंचल भट्टाचार्य

मुख्यसंवाददाता

सत्येंद्र सिंह

छायाकार

नसीम अख्तर

संपर्क : 9431708799

9835437102

ईमेल: navjeewansandesh@gmail.com

सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को फाड़कर... पेज-10

आकाश आनंद अब मायावती के उत्तराधिकारी नहीं, पद भी गया पेज-13

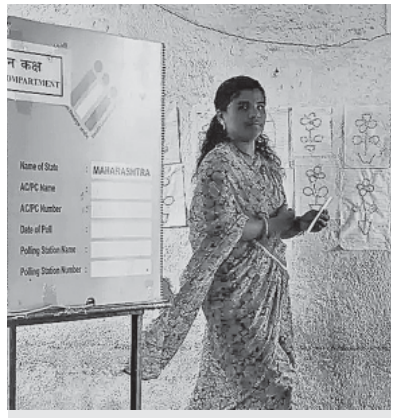

लोकसभा चुनावः पहले चार चरणों में करीब 67%... पेज-09

महिला युवा खिलाड़ियों को निखारने व हॉकी को शीर्ष... पेज-31

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक और प्रकाशक पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रथम तल, होटल आलोका कॉम्प्लेक्स रेडियम रोड, समीप कचहरी चौक, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा मैसर्स डी।,बी। कॉर्प लि। प्लॉट नंबर 535 व 1272, लालगुटवा, पुलिस स्टेशन रातू रांची से मुद्रित।

संपादक : प्रभात मजुमदार* (*संपादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी)

आरएनआई नं.: JHAHIN/2021/83133

संपादकीय

देश के बेरोजगारों में 80 फीसदी युवा

हमारे यहां साधारण बोल चाल की भाषा में कहा जाता है जो जितना ज्यादा पढ़ा-लिखा है, उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ज्यादा है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ताजा रिपोर्ट भी यही कहती है कि देश के बेरोजगारों में 80 फीसदी युवा हैं.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल बेरोजगारों में 80 फीसदी युवा हैं. 'द इंडिया इंपलॉयमेंट रिपोर्ट 2024' के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 30 फीसदी बढ़ चुकी है. साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2 फीसदी थी जो 2022 में बढ़कर 65.7 फीसदी हो गई.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट (आईएचडी) ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट कहती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है.

रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया कि साल 2000 से 2019 के बीच युवाओं के बीच बेरोजगारी लगातार बढ़ी जबकि कोविड महामारी के बाद बेरोजगारी दर में कमी आई.

नागेश्वरन ने कहा, "साल 2000 से 2019 के बीच युवाओं में बेरोजगारी दर 5.7 फीसदी से बढ़कर 17.5 फीसदी हो गई. लेकिन 2022 में यह कम होकर 12.4 फीसदी पर आ गई."

सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रैजुएट डिग्री धारकों में पाई गई. इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित समूह था. 2022 में ऐसी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले पांच गुना ज्यादा थी जो ना तो कोई नौकरी कर रही थीं और ना ही किसी तरह की पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रही थीं.

ऐसी महिलाओं की संख्या 48.4 फीसदी थी जबकि पुरुषों की मात्र 9.8 फीसदी. यानी बेरोजगारों में महिलाएं लगभग 95 फीसदी थीं.

रिपोर्ट कहती है, "युवा महिलाओं के बेरोजगार होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है. 20-24 वर्ष और 25-29 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में यह चलन सबसे ज्यादा पाया गया है."

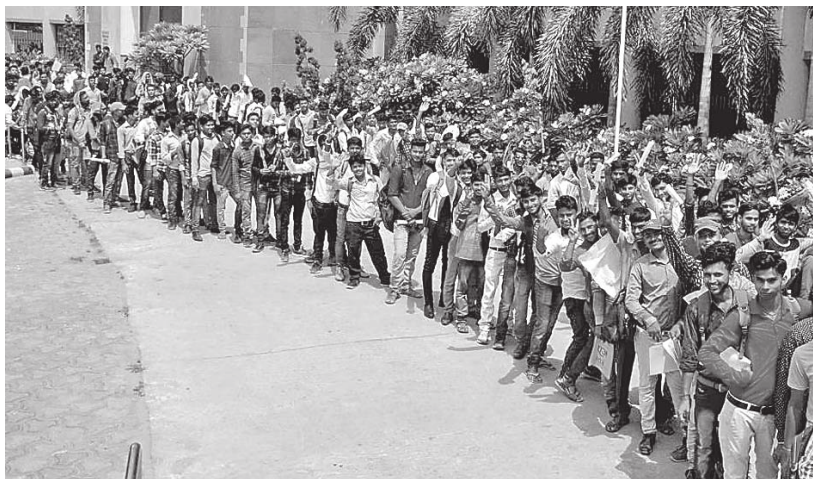

भारत में रोजगार मुख्यतया या तो अनौपचारिक है या फिर लोग अपना काम कर रहे हैं. साल 2000 से 2022 के बीच औपचारिक नौकरी कर रहे लोगों की संख्या मात्र 10 फीसदी रही जबकि 90 फीसदी लोग या तो अपना काम कर रहे हैं या फिर अनौपचारिक रोजगार कर रहे हैं.

साल 2000 के बाद से औपचारिक रोजगार का अनुपात लगातार बढ़ रहा था लेकिन 2018 के बाद इसमें भारी गिरावट आई है. ठेके पर आधारित नौकरियों में इजाफा हुआ है जबकि बहुत कम लोग नियमित और लंबी अवधि के अनुबंध वाली नौकरियों में हैं.

रिपोर्ट कहती है, "नौकरीपेशा लोगों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जिन्हें लंबी अवधि के अनुबंध मिले हैं." लेकिन चिंता की बात यह बताई गई है कि स्थायी नौकरीपेशा लोगों की आय 2019 के बाद से या तो स्थिर रही है या फिर कम हुई है. 2012 से 2022 के बीच अनौपचारिक रोजगार करने वालों की आय में कुछ वृद्धि हुई है.

भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देशों में से एक है और इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े लाभ के रूप में देखा जाता है लेकिन आईएलओ की रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि अधिकतर युवाओं में जरूरी कौशल की कमी है. रिपोर्ट बताती है कि 75 फीसदी युवा ईमेल में अटैचमेंट के साथ डॉक्यूमेंट भेजने तक में सक्षम नहीं हैं. 60 फीसदी युवा कंप्यूटर पर कॉपी-पेस्ट जैसे बहुत सामान्य काम भी नहीं कर पाते जबकि 90 फीसदी युवाओं को स्प्रैडशीट पर गणित के फॉर्म्युलों का प्रयोग करना नहीं आता.

2021 में भारत में युवाओं की आबादी 27 फीसदी थी जो 2036 तक घटकर 21 फीसदी हो जाएगी. यानी हर साल 70 से 80 लाख युवा रोजगार चाहने वालों की लाइन में जुड़ रहे हैं. लेकिन आमतौर पर उपलब्ध रोजगार कम गुणवत्ता वाला है और अधिकतर अनौपचारिक काम ही उपलब्ध है. नागेश्वरन ने कहा कि फिलहाल नौकरियां देने का ज्यादातर काम सरकार ने संभाल रखा है जबकि उद्योग जगत को इस मामले में बढ़त लेने की जरूरत है. साथ ही, रिपोर्ट में गैर-कृषि रोजगार बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया गया है, ताकि आने वाले सालों में बेरोजगारों की लाइनों को और लंबा होने से रोका जा सके.

वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार किया नामांकन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। हलफनामे के मुताबिक, पीएम मोदी के पास न कोई घर है न जमीन और न ही कार। 2019 में उनके पास गांधीनगर में 1.10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन इस बार उसका जिक्र नहीं है। पीएम ने 15 साल से कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदी।

मोदी के पास 52 हजार 920 रुपए कैश है। उन्होंने कुल 3.02 करोड़ की संपत्ति बताई है। 5 साल में यह संपत्ति 87 लाख रुपए बढ़ी। वाराणसी से अपने पहले चुनाव (2014) में मोदी ने अपनी कुल संपत्ति 1.65 करोड़ रुपए बताई थी। दूसरे चुनाव (2019) में यह 2.15 करोड़ हो गई थी। पीएम ने मोबाइल नंबर भी बताया है। पीएम ने अपना एड्रेस- सी/1, सोमेश्वर टेनमेंट्स, रानीप, अहमदाबाद बताया है। नामांकन पत्र में पत्नी जशोदाबेन का नाम लिखा है। हालांकि, पत्नी की आय की जानकारी नहीं दी। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अक्टूबर 2002 में उन्होंने एक जमीन खरीदी थी। इसमें तीन हिस्सेदार थे। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू यानी कीमत 1.10 करोड़ रुपए थी।

मोदी ने यह जमीन मानमंदिर फाउंडेशन को दान कर दी, जिस पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। इसलिए, इस बार उनकी अचल संपत्ति शून्य हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के नाम किसी भी तरह की कृषि या गैर कृषि भूमि और कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। मोदी के पास 4 अंगूठी हैं। 2014 और 2019 में भी 4 सोने की अंगूठी थीं। इनका वजन 45 ग्राम है। 2019 में इस गोल्ड की कीमत 1.13 लाख रुपए बताई थी। 5 साल में यह कीमत बढ़कर 2.67 लाख रुपए हो गई।

पीएम ने बॉन्ड, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं किया है। पोस्ट ऑफिस में 9.12 लाख रुपए की एनएससी है। 2019 में एनएससी में 7.61 लाख रुपए और 1.90 लाख का जीवन बीमा था। हालांकि, इस बार जीवन बीमा नहीं बताया है।

52 हजार 920 रुपए कैश: प्रधानमंत्री मोदी के पास 2019 में 38 हजार 750 रुपए कैश था, जबकि अब उनके पास 52 हजार 920 रुपए कैश है। मोदी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गांधीनगर शाखा के बैंक अकाउंट में 73 हजार 304 रुपए कैश जमा है। वहीं वाराणसी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7 हजार रुपए जमा है। साथ ही उसी बैंक में 2 करोड़ 85 लाख 60 हजार 338 रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है। 2019 में नरेंद्र मोदी के पास करीब 1.27 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट था।

मोदी ने कुछ पैसा सेविंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी लगा रखा है। हलफनामे के मुताबिक, पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9 लाख 12 हजार 398 रुपए जमा किए हैं। पहले उनके नाम करीब 2 लाख रुपए वैल्यू की एलआईसी पॉलिसी भी थी। इसके अलावा 2012 से 20 हजार रुपए का एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (टैक्स सेविंग) था, जो अब नहीं है।

हलफनामे के अनुसार

- फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के मुकाबले 2022-23 में पीएम नरेंद्र मोदी की कमाई दोगुनी बढ़ गई है। 2018-19 में पीएम ने अपनी इनकम 11.14 लाख रुपए रुपए घोषित की थी, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में उनकी इनकम ₹23.57 लाख रही।

- 2019-20 में उनकी इनकम 17.21 लाख रुपए, 2020-21 में 17.08 लाख रुपए और 2021-22 में 15.42 लाख रुपए थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी और बैंक इंटरेस्ट को उनकी कमाई का जरिया बताया है।

- पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3 लाख 33 हजार 179 रुपए का इनकम टैक्स भरा है।

- पीएम मोदी के पास किसी भी तरह के हथियार नहीं है। वहीं उनके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं है।

कांग्रेस इस बार चुनाव में 400 से कम सीटों पर

कांग्रेस इस बार सिर्फ़ 328 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। इतनी कम संख्या में सीटों पर इससे पहले इसने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि, इसने 330 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सूरत और इंदौर सीट पर आखिरी क्षण में इसके उम्मीदवारों के पाला बदलने व चुनाव से हटने से दो सीटें कम हो गईं। तो सवाल है कि आख़िर इस बार इसकी क्या मजबूरी हो गई कि वह पहली बार 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है?

इस सवाल का जवाब है इंडिया गठबंधन। बीजेपी और पीएम मोदी के चुनावी जीत के रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया और कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के लिए 101 सीटें छोड़ दीं। इसी वजह से कांग्रेस 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार 93 कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार पार्टी ने देश भर के कुल 12 राज्यों में 2019 की तुलना में कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

इस बार जिन राज्यों में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के लिए सबसे ज्यादा सीटें छोड़ी हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक रिपोर्ट छापी है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में हुई है। यहाँ 2019 में पार्टी ने राज्य की 80 सीटों में से 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल एक सीट रायबरेली में सोनिया गांधी जीती थीं। इस बार इसका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है और इसलिए कांग्रेस 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी सबसे बड़ी गिरावट पश्चिम बंगाल में है। कांग्रेस ने 2019 में 42 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी ने वाम दलों के साथ समझौते तहत सिर्फ 14 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 2019 का चुनाव एनसीपी के साथ गठबंधन में लड़ा था। लेकिन शिवसेना (यूबीटी) के साथ भी गठबंधन होने के कारण पिछली बार की 25 सीटों की तुलना में कांग्रेस इस बार 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है।

आप के साथ गठबंधन के कारण पार्टी को हरियाणा में एक और गुजरात में दो सीटें दी गईं। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में उसने सीपीएम और सीपीआई को दो सीटें दी हैं। असम में एक सीट स्थानीय पार्टी असम जातीय परिषद को दी गई।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, लेकिन सपा उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया। राजस्थान में पार्टी ने सहयोगियों को तीन सीटें- सीकर से सीपीएम को, नागौर से हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को और बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी को दीं।

त्रिपुरा में उसने त्रिपुरा पूर्व सीट सहयोगी सीपीएम को दे दी है। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस ने 2019 में पांच सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार वह लद्दाख सीट समेत तीन सीटों पर मैदान में है।

- दिल्ली में आप के साथ गठबंधन होने की वजह से पिछली बार की 7 की तुलना में इस बार कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

कर्नाटक, ओडिशा में सीटें बढ़ीं : कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक और ओडिशा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक में पार्टी 2019 की 21 सीटों की तुलना में इस बार सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार इसने तत्कालीन सहयोगी जद (एस) के लिए बाकी सीटें छोड़ी थीं। ओडिशा में पार्टी 2019 की 18 सीटों की तुलना में इस बार 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसने 2009 में 440, 2014 में 464 और 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा।

‘जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी’ पर आई रिपोर्ट और उससे जुड़े सवाल

▪ इमरान क़ुरैशी

लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल ने भारत की ‘जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी’ पर एक वर्किंग पेपर जारी किया है. इसकी मंशा पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं. इस वर्किंग पेपर का शीर्षक है ‘शेयर ऑफ़ रिलीजियस माइनॉरिटीजः ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस (1950-2015).’ एक्सपर्ट इस रिपोर्ट की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भारत में बहुसंख्यकों (हिंदू) और अल्पसंख्यकों (मुसलमान) की आबादी की बढ़ोतरी और गिरावट की बात जिन पैमानों पर कर रही है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. वर्किंग पेपर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि, “1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82 प्रतिशत घटी है. 1950 में देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.68 प्रतिशत थी और 2015 में ये हिस्सेदारी 78.06 हो गई थी. 1950 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 9.84 था और 2015 में ये 14.09 प्रतिशत हो गया. 1950 की तुलना में ये मुसलमानों की आबादी में 43.15 प्रतिशत बढ़ोतरी है.”

दरअसल, यह आबादी के बढ़ने का प्रतिशत नहीं बल्कि हिस्सेदारी में बदलाव का प्रतिशत है, लेकिन कई चैनलों ने इसे इसी भ्रामक तरीके से दिखाया जिसकी आलोचना पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने की है.

पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुटरेजा कहती हैं कि 2011 की जनगणना बताती है कि ‘बीते तीन दशकों में मुसलमानों की जन्म दर घटी है.’

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर रहे पुरुषोत्तम एम कुलकर्णी जनसंख्या से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं. उन्हें भी इस निष्कर्ष पर एतराज़ है.

प्रोफ़ेसर कुलकर्णी ने बीबीसी हिंदी को बताया, “हम साधारण तौर पर प्रतिशत का प्रतिशत नहीं निकालते हैं.”

बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज में जेआरडी टाटा चेयर के विजिटिंग प्रोफेसर नरेंद्र पाणि ने बीबीसी को बताया, “अगर समुदाय की तादाद कम है तो प्रतिशत के हिसाब से देखने पर बदलाव बहुत बड़ा लगेगा. ऐसे ही किसी समुदाय की तादाद अधिक होने पर कोई भी बदलाव प्रतिशत के हिसाब से छोटा ही लगेगा. ये बुनियादी अंकगणित है.”

वर्किंग पेपर में क्या लिखा है?: पेपर का आधार ये है कि एक समाज जो “अल्पसंख्यकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, वहाँ तीन दशकों की अवधि में उनकी संख्या वृद्धि में अधिक स्थिरीकरण की संभावना है.” इसी तरह से अगर एक समाज प्रतिकूल वातावरण बनाए या अल्पसंख्यकों को ‘वस्तुओं और सेवाओं’ से वंचित रखे तो “कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी घटेगी.”

संक्षेप में समझें तो इससे इस बात का संकेत मिलता है कि समाज में अल्पसंख्यकों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है. इस वर्किंग पेपर को डॉक्टर शमिका रवि, अब्राहम जोस और अपूर्व कुमार मिश्रा ने लिखा है.

पेपर में दुनिया के 167 देशों में जनसंख्या के हालात पर गौर किया गया है जहां 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यकों (धर्म के आधार पर) की आबादी में लगभग 22 प्रतिशत गिरावट आई है. रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ मुसलमानों की ही आबादी नहीं बढ़ी है बल्कि ईसाइयों की भी बढ़ी है. पेपर में लिखा है कि भारत की आबादी में ईसाइयों का प्रतिशत 1950 में 2.25 था और ये 2015 में 2.36 प्रतिशत हो गया. ये इस दौरान ईसाइयों की जनसंख्या में कुल 5.38 की बढ़ोतरी है. पेपर में ये भी लिखा है कि 1950 में सिख भारत की कुल जनसंख्या के 1.24 प्रतिशत थे. साल 2015 में सिखों की भागीदारी 1.85 प्रतिशत हो गई है. ये सिखों में आबादी में 6.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

पेपर के मुताबिक ऐसे ही बौद्ध धर्म के मानने वालों की आबादी का देश की कुल जनसंख्या में हिस्सा बढ़ा है.

पेपर में लिखा है, “लेकिन जैन धर्म को मानने वालों की संख्या कम हुई है. 1950 में जैन देश की कुल आबादी का 0.45 प्रतिशत थे तो 2015 में ये 0.36 ही रह गए हैं. पारसियों की संख्या में इस दौरान 85 प्रतिशत गिरावट आई है. ये 1950 में पारसी 0.03 प्रतिशत थे तो 2015 में 0.004 प्रतिशत ही रह गए थे.” वर्किंग पेपर के मुताबिक़, दक्षिण एशिया में बहुसंख्यकों की आबादी में सर्वाधिक गिरावट (7.82%) भारत में आई है. इसके बाद म्यांमार का नंबर आता है. वहां बहुसंख्यकों की आबादी पिछले 65 वर्षों में 10 प्रतिशत घटी है. अल्पसंख्यकों का म्यांमार की कुल आबादी में प्रतिशत बढ़ा है. वर्किंग पेपर में लिखा है, “भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों और सिखों का देश की कुल आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी है लेकिन जैन और पारसियों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है.”पेपर के मुताबिक, ‘कई हलकों में फिलहाल चल रहे इस शोर शराबे के विपरीत, डेटा के सावधानीपूर्वक किए गए 28 विश्लेषणों से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं बल्कि फल-फूल रहे हैं.’ “दक्षिण एशिया के व्यापक संदर्भ को देखते हुए यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है. दक्षिण एशिया में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी बढ़ी है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक आबादी चिंताजनक रूप से घट गई है.”

इसके क्या परिणाम होंगे?

लेकिन पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पूनम मुटरेजा कहती हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, "बीते तीन दशकों में मुसलमानों की जन्म दर में गिरावट आ रही है."

उनका कहना है, "1981-91 के दौरान मुसलमानों में जन्म दर 35.9 प्रतिशत थी जो 2001-2011 में 24.6 रह गई है. हिंदुओं की तुलना में ये गिरावट अधिक है. इसी पीरियड में हिंदुओं की जन्म दर 22.7 (1981-1991) प्रतिशत से घटकर 16.8 प्रतिशत (2001-2011) हो गई है. इस वक्त हमारे पास 1951 से 2011 के बीच की जनगणना ही उपलब्ध है और ये डेटा इस स्टडी से मिलता जुलता है. इससे संकेत मिलता है कि ये संख्या कोई नहीं है."

पूनम मुटरेजा कहती हैं कि सभी धर्मों को मानने वाले समूहों में टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) घट रहा है. इनमें सबसे अधिक गिरावट 2005-06 से 2019-21 के बीच मुसलमानों में आई है.

"ये गिरावट 1 प्रतिशत है जबकि इसी दौरान हिंदू टीएफआर में 0.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इस ट्रेंड से पता चलता है कि अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लोगों के टीएफआर में गिरावट आ रही है."

पूनम मुटरेजा कहती हैं, "प्रजनन दर का संबंध शिक्षा और आय से है, धर्म से नहीं. जिन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक विकास की स्थिति अच्छी है वहाँ प्रजनन दर कम है. केरल और तमिलनाडु ऐसे ही राज्य हैं. उदाहरण के तौर पर केरल की मुसलमान महिलाओं में प्रजनन दर 2.25 है. ये दर बिहार की हिंदू महिलाओं की 2.88 की प्रजनन दर से कम है."

मीडिया में जिस तरह से इस मुद्दे को रिपोर्ट किया गया है उससे भी मुटरेजा चिंतित हैं. उनका कहना है, "पेपर के निष्कर्षों को गलत रिपोर्ट कर के मुस्लिम आबादी की वृद्धि के संबंध में चिंता फैलाई जा रही हैं. ऐसी व्याख्याएं न केवल गलत हैं बल्कि भ्रामक और आधारहीन भी हैं." मुटरेजा के अनुसार, 65 साल की अवधि में वैश्विक स्तर पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों की हिस्सेदारी में बदलाव पर अध्ययन का इस्तेमाल किसी भी समुदाय के खिलाफ भय या भेदभाव को भड़काने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

"मुस्लिम आबादी में वृद्धि को उजागर करने के लिए मीडिया ने डेटा का सेलेक्टिव चित्रण, गलतबयानी का एक उदाहरण है जो व्यापक जनसांख्यिकीय रुझानों को नजरअंदाज करता है."

1981-91 के दौरान मुसलमानों में जन्म दर 35.9 प्रतिशत थी जो 2001-2011 में 24.6 रह गई है. हिंदुओं की तुलना में ये गिरावट अधिक है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे पुरुषोत्तम एम कुलकर्णी कहते हैं, "जनसंख्या कम नहीं हुई है बल्कि उसकी हिस्सेदारी कम हो गई है. ये कोई नई बात नहीं है. पारसियों और यहूदियों को छोड़कर सभी धर्मों की कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है. यह पाया जाना असामान्य नहीं है कि कुछ धर्मों की वृद्धि दर, कुछ अन्य धर्मों की तुलना में अधिक है."

वे कहते हैं कि सभी राज्यों की आबादी बढ़ती जा रही है, "लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी है और केरल और तमिलनाडु का हिस्सा कम हो गया है. ऐसा नहीं है कि केरल और तमिलनाडु की आबादी कम हो गई है. हिस्सेदारी इसलिए कम हो रही है क्योंकि वहां आबादी बढ़ने की दर उत्तर प्रदेश और बिहार से कम है."

"सारे देश में प्रजनन दर घटी है लेकिन इसे शून्य तक पहुँचने में वक्त लगता है. इसे पॉपुलेशन मूमेंटम कहते हैं. मौजूदा समय में भारत पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल पर है. इसका अर्थ है कि भारत में प्रति महिला 2.1 बच्चे पैदा हो रहे हैं. लेकिन अभी 45 से 50 वर्षों तक वास्तविक ग्रोथ रेट सकारात्मक ही रहेगा. उसके बाद आबादी में गिरावट आनी शुरू होगी."

मुसलमानों के बारे में प्रोफेसर कुलकर्णी कहते हैं, "चूंकि फ़िलहाल उनका ग्रोथ रेट अधिक है तो उसे शून्य तक पहुंचने में अधिक वक्त लगेगा. हिंदुओं के केस में ये 84.6 से 78.6 तक आ पहुँचा है. ये छह प्रतिशत की गिरावट है. लेकिन हम साधारण तौर पर प्रतिशत का प्रतिशत नहीं निकालते हैं."

"मुसलमानों की भारत की कुल आबादी में भागीदारी 9.84 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है. ये करीब 4 फीसदी की बढ़ोतरी है. इसकी गणना (अध्ययन पत्र में) नौ प्रतिशत के चार प्रतिशत, यानी 43 प्रतिशत के रूप में की गई है. वास्तविक तौर पर देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी."

प्रोफेसर पाणि कहते हैं, "साल 2011 की जनगणना में मुसलमानों की जनसंख्या दर में कमी स्पष्ट दिखाई दी थी. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. एक बार जब आप एक निश्चित आर्थिक स्थिति पर पहुँच जाते हैं तो जनसंख्या दर कम होने लगती है. अगर आप चुनाव के बीच में ऐसी स्टडी सार्वजनिक करते हैं तो ये आपकी निराशा का संकेत है."

एक्सपर्ट्स की आलोचना पर बीबीसी ने वर्किंग पेपर के लेखकों में से एक डॉक्टर शमिका रवि से संपर्क कर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की थी लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला.

अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा तो इसे रिपोर्ट में जोड़ दिया जाएगा.

लोकसभा चुनाव: पहले चार चरणों में करीब 67% मतदान

लोकसभा चुनाव के पहले चार चरणों में औसतन 66.95 फीसदी मतदान हुआ। 97 करोड़ में से 45.10 करोड़ वोटर्स ने मतदान किया है। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी।

आयोग के मुताबिक, 13 मई को हुए चौथे चरण के मतदान में 69.16 फीसदी वोटिंग हुई। यह 2019 के लोकसभा चुनावों में इसी (चौथे) चरण की तुलना में 3.65 फीसदी ज्यादा है। चुनाव के तीसरे चरण में 65.69 फीसदी मतदान हुआ, जबकि 2019 चुनाव के तीसरे चरण में 68.4 फीसदी मतदान हुआ था।

543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। 20 मई तक कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर मतदान होगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के बाकी चरणों में फोकस मतदाताओं को जागरूक करने और सुविधाएं देने पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव ने कहा कि यह देखकर खुशी हो रही है कि बड़ी-बड़ी हस्तियां लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही हैं। आयुक्त ने आने वाले चरणों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और मतदान करने की अपील की है।

चुनाव आयोग ने फर्स्ट-सेकंड फेज का फाइनल वोटिंग डेटा जारी किया, विपक्ष का सवाल- इतनी देरी क्यों हुई?

चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी किया था। पहले चरण में 66.14 प्रतिशत और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ। इस पर विपक्षी दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और CPM ने देरी से फाइनल डेटा आने पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना था कि आमतौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटों के भीतर जारी कर दिया जाता है। लेकिन इस बार यह काफी देर से जारी हुआ है।

डेरेक ओ ब्रायन कहा- आंकड़े में लगभग 6 प्रतिशत का फर्क है : टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सेकेंड फेज के खत्म होने के चार दिन बाद फाइनल डेटा जारी किया। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़े में 5.75% की बढ़ोतरी हुई है। क्या यह नॉर्मल है? या फिर कुछ मिस कर रहा हूं?

लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 13 मई को 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। 67.71% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78.44% और सबसे कम जम्मू-कश्मीर में 37.98% मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ।

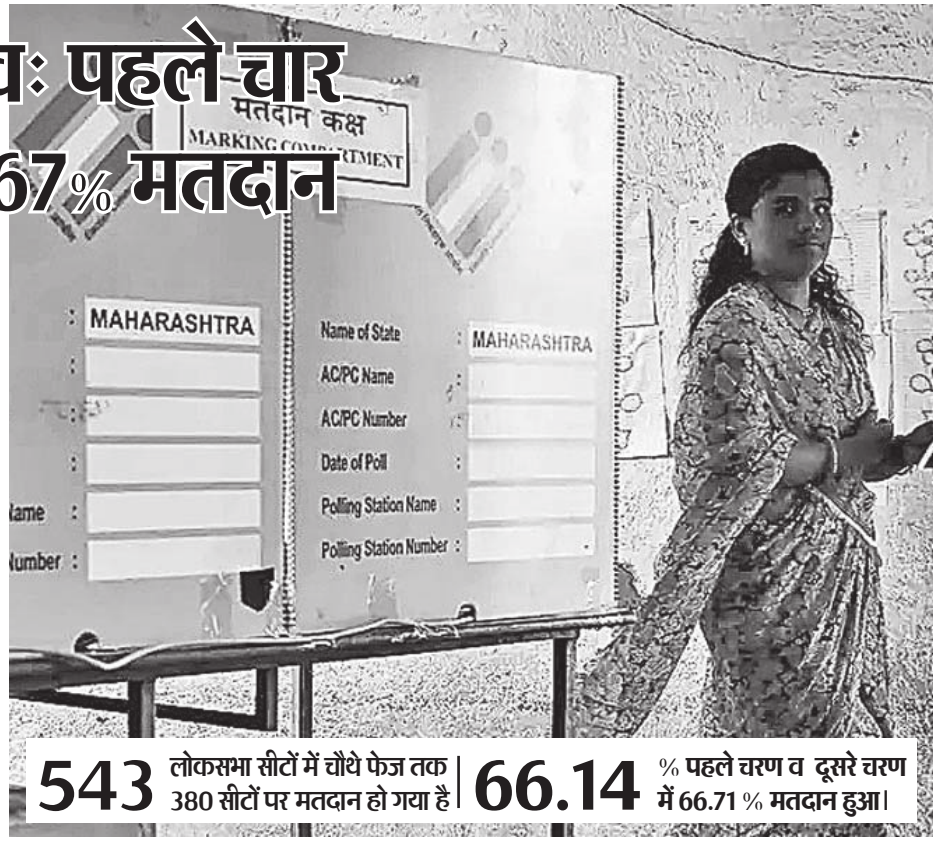

543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है | **66.14** % पहले चरण व दूसरे चरण में 66.71 % मतदान हुआ।

कम होता मतदान, किसका नुकसान

▪ चारु कार्तिकेय

लोकसभा चुनावों के पहले तीन चरणों की तरह ही चौथे चरण में भी 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत कम रहा. बीजेपी का कहना है कि इससे विपक्ष को चिंता होनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नए विज्ञापन कुछ और ही कहानी कह रहे हैं. चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मतदान के चौथे चरण में अभी तक करीब 67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक 2019 में इन्हीं सीटों में मतदान प्रतिशत 69.6 रहा था, यानी इस बार का आंकड़ा करीब दो प्रतिशत कम है.

वहीं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार का दावा है कि 2019 में इन सीटों में 68.8 प्रतिशत मतदान हुआ था, यानी इस बार से सिर्फ करीब एक प्रतिशत ज्यादा. सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल (78.44 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (78.25 प्रतिशत) में हुआ और सबसे कम जम्मू और कश्मीर (37.98 प्रतिशत) में हुआ. जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा सीट की कहानी दिलचस्प है.

श्रीनगर में इस बार 38 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो वहां के लिए बीते कई चुनावों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन है. आखिरी बार इस तरह का बेहतर मतदान प्रतिशत 1996 में दर्ज किया गया था, जब करीब 40 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था.

2019 में यहां सिर्फ 14.4 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था. हालांकि पिछले चुनावों और इन चुनावों में एक बड़ा फर्क है. इन चुनावों से पहले श्रीनगर लोकसभा सीट का परिसीमन कर दिया गया था, जिस वजह से इस बार इसमें कई नई विधानसभा सीटें जुड़ गई हैं.

चौथे चरण के साथ लोकसभा की 543 में से 379 सीटों, यानी दो तिहाई से ज्यादा पर मतदान पूरा हो गया है. चारों चरणों में मतदान 2019 के मुकाबले कम रहा. राजनीतिक पार्टियां और विश्लेषक सभी इसे लेकर चिंतित हैं. जानकारों का मानना है कि यह मतदाताओं के मन में मतदान को लेकर उत्साह की कमी को दर्शाता है. पार्टियों को चिंता है कि मतदान करने नहीं जाने वाले मतदाता कहीं उनके समर्थक तो नहीं थे. विपक्षी पार्टियां इसे अपनी जीत का परिचायक मान रही हैं, जबकि बीजेपी इस बात से असहमत है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि कम मतदान से विपक्ष को चिंता होनी चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कि विपक्ष के समर्थकों में उत्साह नहीं है.

हालांकि बीजेपी के नए विज्ञापन कम मतदान की ही बात कर रहे हैं. एक्स पर पार्टी के हैंडल से एक वीडियो विज्ञापन पोस्ट किया गया जिसमें लोकप्रिय अभिनेत्री रूपाली गांगुली लोगों को "जाना है तो जाना है" नारे के साथ मतदान के लिए प्रेरित करती नजर आ रही हैं.

गांगुली हाल ही में बीजेपी में शामिल भी हुई थीं. विज्ञापन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं, "जो इतनी मेहनत करते हैं, भागादौड़ी करते हैं हमारे लिए...तो हम उनके लिए चार कदम चल कर वोट देने तो जा ही सकते हैं ना."

सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेकेंगे : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झांसी में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा- भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं। हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी। उन करोड़ों महिलाओं के खाते में एक लाख रुपए भेजे जाएंगे। यानी महीने 8500 रुपये खाते में खटाखट-खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था।

राहुल ने कहा- अग्निवीर योजना को हम फाड़कर कचरे में फेंक देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अधिक, अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीबों, किसानों, कमजोर लोगों की सरकार बननी चाहिए, अंबानी-अडानी की सरकार हटाई जानी चाहिए।

2022 को लागू हुई थी स्कीमः केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर स्थायी करने पर विचार करेंगे। 25% 'अग्निवीरों' को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा।

सरकार ने स्कीम में बदलाव की बात कहीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 मार्च 2024 को कहा था कि कि सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'सेना को युवाओं की जरूरत है। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे।' इस स्कीम में सिर्फ 4 साल की सर्विस को विपक्ष ने युवाओं के साथ धोखा बताया था।

रैली में अखिलेश ने कहा- किसानों की आय का सारा पैसा भाजपा की जेब में जा रहा है। सब कुछ इस सरकार में महंगा हो गया है। हर बार जब परीक्षा हुई, पेपर लीक कर दिया गया। वैक्सीन का सच तो आप जानते ही होंगे।

सुशील कुमार मोदी का निधनः बिहार की राजनीति के एक अध्याय का अंत

- 1990 में सुशील कुमार मोदी ने पटना केन्द्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे.
- 1995 और 2000 का भी चुनाव वो इसी सीट से जीते.
- साल 2004 में उन्होंने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था.
- साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उपमुख्यमंत्री बने.
- साल 2005 से 2013 और फिर 2017 से 2020 के दौरान वो बतौर उपमुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाते रहे. इस दौरान वो पार्टी में भी कई दायित्व संभालते रहे.

बिहार की राजनीति में करीब पांच दशक से अलग-अलग भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार मोदी नहीं रहे. बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने 13 मई सोमवार को अंतिम सांसें लीं. वो कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.

लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुशील मोदी ने अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक की थी.

उन्होंने एक्स पर लिखा था, ''मैं पिछले छह महीने से कैंसर से जंग लड़ रहा हूं. अब मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए. मैं लोकसभा चुनाव में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा.''

इसके बाद से ही वो राजनीति और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे

सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जताया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, ''पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है. बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है. आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए, उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी."

"वे बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे. राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी. उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफ़ी सराहनीय कार्य किए. जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी. शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं.

लालू यादव और सुशील कुमार मोदी, छात्र राजनीति से लेकर अब तक क़रीब 50 साल से एक दूसरे की राजनीति देखते आए थे.

सुशील कुमार मोदी के निधन पर लालू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने लिखा है कि बीते 51-52 वर्षों यानी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के समय से वो उनके मित्र थे. वे एक जुझारू, समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे. ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे.

सुशील मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे. उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में हुई. उस वक़्त वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए. 1973 में वो महामंत्री चुने गए.

उस वक़्त पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे.भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतकार और संघ विचारक रहे केएन गोविंदाचार्य को सुशील कुमार मोदी का मेंटर माना जाता है.

उन्होंने एक बार कहा था, ''मैंने सुशील मोदी को 1967 से देखा है. उस वक़्त भी आप उनके व्यक्तित्व को अलग से नौजवानों की भीड़ में चिह्नित कर सकते थे. सादगी, मितव्ययिता, किसी काम को बहुत केन्द्रित और अनुशासित होकर करना उनकी खासियत थी."

जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. आपातकाल में वे 19 महीने जेल में रहे. 1977 से 1986 तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे.

-उन्होंने कहा था, ''देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे, जिनको पार्टी ने इतना मौका दिया है. मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है. मैं तीन बार विधायक, एक बार लोकसभा, 6 साल तक विपक्ष का नेता बिहार विधानसभा में, 6 साल तक विधान परिषद में विपक्ष का नेता रहने का मौका मिला है. और बिहार के अंदर क़रीब 12 साल तक नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला है."

"मुझे पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम करने का मौका मिला है. राजनीति में कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है लेकिन सामाजिक तौर पर आजीवन काम कर सकता है. मैं संकल्प लेता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूंगा.''

इस भाषण के आखिर में उन्होंने बजट भाषण को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में कराने की सलाह दी थी. सुशील कुमार मोदी के जानने वाले उन्हें समय से आगे रहने

वालों में से एक मानते हैं. सुशील कुमार मोदी के हाथ में टैबलेट उस वक़्त देखा गया, जब राज्य के बहुत सारे नेताओं के लिए ये किसी अजूबे जैसा था.

सुशील मोदी के साथ लंबे समय तक काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर ने बताया था कि कैसे 1995 में भी उनके पास ताइवान का एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, सुशील मोदी अपने रोजाना के काम को उसमें दर्ज करते थे.

सुशील कुमार मोदी ने अंतरधार्मिक शादी की थी. ट्रेन से एक लंबे सफ़र में उनकी मुलाक़ात जेसी जॉर्ज से हुई थी और 1987 में दोनों ने शादी कर ली.

आशीर्वाद देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और कर्पूरी ठाकुर भी शादी में शरीक हुए थे. उनके दो बेटे हैं.

लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू करने वाले सुशील मोदी ने उन्हें जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी. इस बात को उनकी पर्सनल वेबसाइट पर भी प्रमुखता से जगह दी गई है.

साथ ही वो 'लालू लीला' नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े कथित घोटालों के बारे में लिखा है.

वो साल 1996 में चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे.

साल 2015 में जेडीयू-आरजेडी की सरकार बनने के बाद, सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया. उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई. नई सरकार 27 जुलाई को बनी जिसमें सुशील कुमार मोदी फिर उपमुख्यमंत्री बने.

बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी कहते हैं कि सुशील मोदी पर अक्सर बीजेपी के लोग संगठन को कमजोर करने का आरोप लगाते थे. पत्रकार अभिनव गोयल के साथ बातचीत में वो कहते हैं, "बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए थे कि सुशील मोदी, नीतीश कुमार के लक्ष्मण बनकर उन्हें ही सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं. यही वजह थी कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें किनारे कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी के लोगों को लगता था कि उनकी वजह से वे अकेले सरकार नहीं बना पा रहे हैं."

बिहार में शराबबंदी में भी सुशील मोदी की भूमिका का ज़िक्र कन्हैया भेलारी करते हैं. वे कहते हैं कि नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे लेकिन सुशील मोदी ने ललकारते हुए नीतीश कुमार को पूर्ण शराबबंदी करने के लिए कहा, जिसके कुछ ख़ास नतीजे देखने को नहीं मिले. वे कहते हैं, "सुशील मोदी जानते थे कि पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं होगी, बावजूद इसके उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर इसे लागू करवाया. इससे राज्य में शराब माफिया बढ़े और कई लोगों की मौतें हुईं." वे कहते हैं कि जब सृजन घोटाले में सुशील मोदी की बहन पर आरोप लगे तो वो काफी दुखी हुए. भेलारी कहते हैं, "सृजन घोटाले के समय वे परेशान हुए और उन्होंने सफाई दी थी कि उनकी बहन अलग रहती है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है."

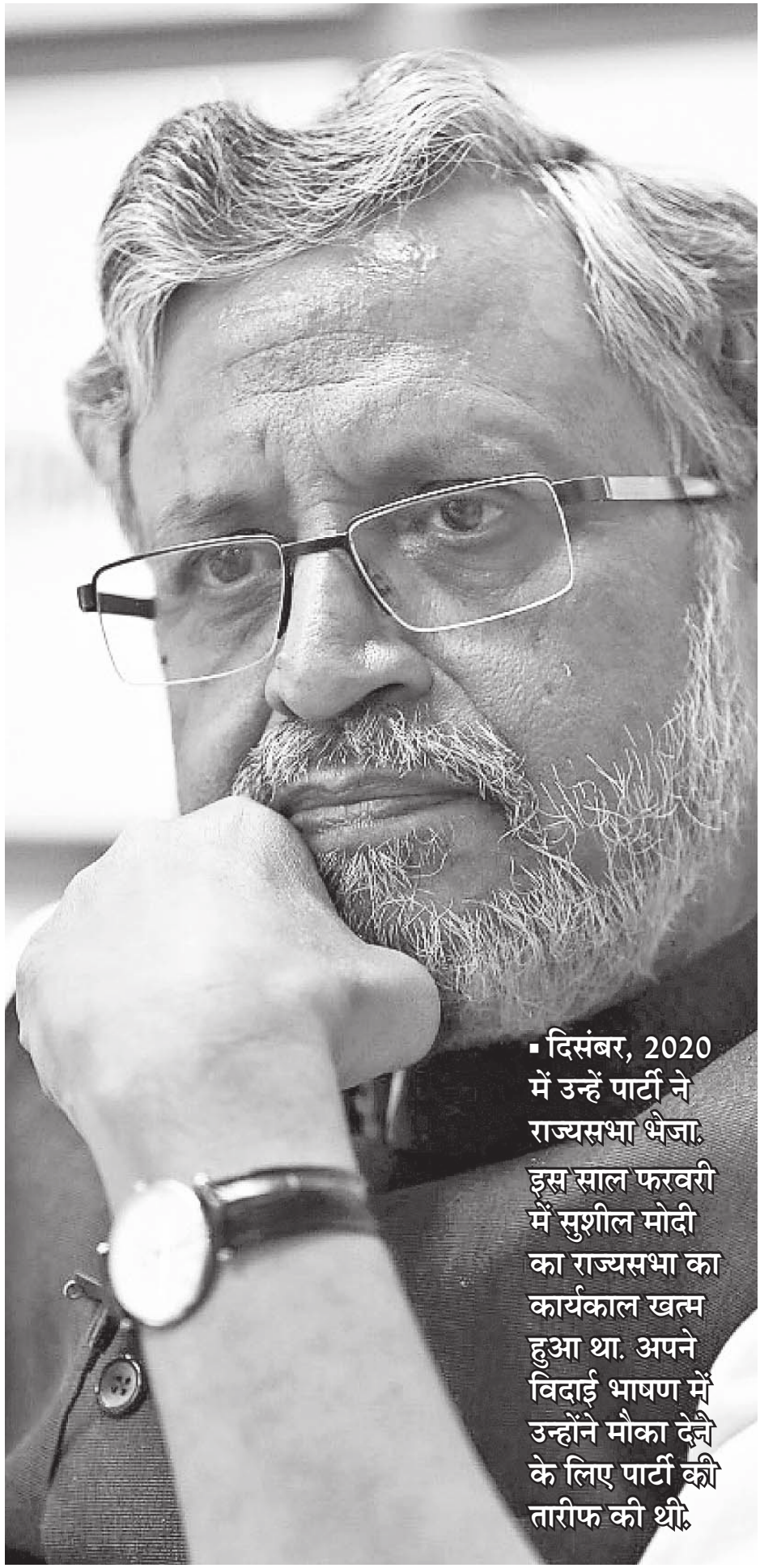

▪ दिसंबर, 2020 में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा. इस साल फरवरी में सुशील मोदी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था. अपने विदाई भाषण में उन्होंने मौका देने के लिए पार्टी की तारीफ की थी.

आकाश आनंद अब मायावती के उत्तराधिकारी नहीं, पद भी गया

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आकाश ने आरोप लगाया था कि 'भाजपा चोरों की पार्टी है जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ₹16,000 करोड़ लिए।'

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह घोषणा पिछले साल दिसंबर महीने में इस लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की एक बैठक के दौरान की गई थी।

लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। मायावती ने हाल में बीजेपी पर हमलावर रहे अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फ़ैसला तक वापस ले लिया है। इसके अलावा आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया है।

अपने इस फ़ैसले को लेकर मायावती ने पार्टी को खड़ा करने और डॉ. भीमराव आंबेडकर के स्वाभिमान के लिए कांशीराम और खुद की मेहनत का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसी के तहत आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने कहा कि अब वह अपना फैसला वापस ले रही हैं। इसके पीछे वजह उन्होंने आकाश आनंद में पूरी परिपक्वता के अभाव को बताया है।

इसके साथ ही मायावती ने कहा है कि भले ही आकाश को हटाया गया है, लेकिन इनके पिता आनन्द कुमार पार्टी व मूवमेन्ट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा, 'बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेन्ट के हित में एवं बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर के कारवाँ को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है।'

उन्होंने कहा, 'बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेन्ट है जिसके लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिन्दगी समर्पित की है।' पिछले दिनों आकाश आनंद के निशाने पर थी बीजेपी

आकाश आनंद के ख़िलाफ़ मायावती की यह कार्रवाई तब की गई है जब हाल ही में यूपी में दिया उनका एक भाषण काफी सुर्खियों में था। 28 अप्रैल को सीतापुर में एक चुनावी रैली में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में आकाश आनंद और चार अन्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। तब उन्होंने कहा था, 'यह सरकार बुलडोजर सरकार और गद्दारों की सरकार है। जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और बुजुर्गों को गुलाम बनाती है वह आतंकवादी सरकार है। तालिबान अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चलाता है।' अपने संबोधन में आकाश आनंद ने राज्य में 16,000 अपहरण की घटनाओं की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था और सरकार पर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप भी लगाया था।

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह घोषणा पिछले साल दिसंबर महीने में इस लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की एक बैठक के दौरान की गई थी। बसपा प्रमुख ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाहर के राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी थी।

आकाश आनंद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा था जो पार्टी नेता के रूप में बसपा अध्यक्ष का कार्यभार संभालता। उनके बारे में कहा जाता था कि वह पिछले साल से पार्टी मामलों के प्रभारी भी थे।

2016 में बसपा में शामिल होने के बाद आकाश आनंद को 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया था। मायावती ने 2019 में अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था और भतीजे आकाश को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया था। 2022 में राजस्थान के अलवर में आकाश आनंद अपनी पदयात्रा के बाद मायावती के सर्कल में दिखने लगे थे।

वंशवादी राजनीति की हमेशा बड़ी आलोचक रहीं मायावती के लिए तब आकाश आनंद पर फैसला लेना आसान काम नहीं रहा होगा। और इसका अंदाजा मायावती को 2019 में अपने जन्मदिन पर अखबारों में आई तस्वीरों के बाद लग गया होगा। दरअसल, 2019 में मायावती के जन्मदिन पर उनके साथ दिखा एक नौजवान अचानक राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया था। उसके बारे में हुई तमाम तरह की चर्चाओं पर बीएसपी सुप्रीमो ने तब जवाब दिया था कि वह उनका भतीजा आकाश आनंद है और वह उसे बीएसपी मूवमेंट में शामिल करेंगी। तब आकाश सिर्फ 24 वर्ष के थे।

मायावती ने तब कहा था, 'मैं कांशीराम की चेली हूं और जैसे को तैसा जवाब देना जानती हूं। मैं आकाश को बीएसपी मूवमेंट में शामिल करूंगी और अगर मीडिया के कुछ जातिवादी व दलित विरोधी तबके को इस पर आपत्ति है तो रहे, हमारी पार्टी को इसकी कोई चिंता नहीं है।'

चुनाव के बीच बदलते ममता के सुर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बाहर से समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। आइए, जानते हैं कि ममता बनर्जी के बयान के क्या सियासी मायने हैं?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के लोकसभा चुनाव 2024 के बीच अचानक सुर बदल गए हैं। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कवायद शुरू की थीं। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि इंडिया गठबंधन का नाम भी उन्होंने दिया है, लेकिन बीच में ही ममता बनर्जी ने अपना रास्ता अलग कर लिया और पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। इस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का मुकाबला इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस-लेफ्ट और बीजेपी के साथ हो रहा है।

चुनाव आयोग ने राज्य में सात चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। सात चरणों में चार चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। चार चरणों में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर मतदान हो चुका और अभी भी दो तिहाई सीटें यानी 24 सीटों पर मतदान बाकी है। ऐसे में बुधवार को हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए एक अहम बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करेंगी और बाहर से समर्थन करेंगी।

ममता बनर्जी ने बंगाल में माकपा और कांग्रेस को भाजपा की 'बी' टीम करार दिया, लेकिन साथ में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वह इंडिया गठबंधन के साथ हैं। चुनाव के बीच में ममता बनर्जी के बयान को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच में क्यों इंडिया गठबंधन को लेकर अपने सुर बदल लिया है?

18 सीटों पर हो चुकी है वोटिंग : पश्चिम बंगाल में अभी चार चरणों में कुल 18 सीटों पर मतदान हुए हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में 81।91% मतदान हुए हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में दार्जिलिंग, रायगंज, बालुरघाट में 76. 58%, 7 मई को मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद में 77.53% और 13 मई को बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, वर्धमान पूरबा, बर्धमान-दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम में 80.22% मतदान हुए हैं। पहले तीन चरणों में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान हुए हैं। वे उत्तर बंगाल या उनसे सटी हुए सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की आठ लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने सात पर जीत हासिल की थी। यह इलाका मूलतः आदिवासी प्रभाव वाली सीटें हैं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन सीटों पर बीजेपी का प्रभाव अभी भी कायम है। उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय और राणाघाट और कृष्णानगर लोकसभा की सीटों पर क्रमशः राजवंशी समुदाय और मतुआ समुदाय

ममता के गढ़ में अगली लड़ाई

पश्चिम बंगाल में अगले तीन चरणों में 22 सीटों पर मतदान होने हैं. पांचवें चरण में 20 मई को बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग, 25 मई को छठे चरण में तमलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, बिष्णुपुर व सातवें. 1 जून को दम दम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर में मतदान हैं.

का प्रभाव है। बीजेपी ने राजवंशी समुदाय के अनंत महाराज को राज्यसभा का सांसद बनाकर और मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू कर उनका दिल जीतने की कोशिश की है। ऐसे में उत्तर बंगाल ममता बनर्जी के लिए केवल अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने की लड़ाई थी।

ये सीटें मूलतः दक्षिण बंगाल, मध्य बंगाल और राज्य की राजधानी कोलकाता से सटी हुई लोकसभा सीटें हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है और लंबे समय से टीएमसी इन सीटों पर जीत हासिल करती रही हैं। इस तरह से अगले तीन चरणों में राज्य में जो चुनावी जंग होने जा रही है। वह मूलतः ममता के गढ़ में होने जा रही है और ममता बनर्जी के लिए यह चुनौती है कि वह अपने गढ़ को कैसे बचाएंगी?

मुस्लिम वोटों के बंटने की आशंका : पिछले चुनाव 2019 में राज्य की कुल 42 सीटों में से बीजेपी ने पहली बार 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी की सीटों की संख्या घटकर 22 हो गयी थी। कांग्रेस को दो सीटें मिली थी और लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिली थी। पिछला लोकसभा सीटों सभी पार्टियों ने अलग-अलग लड़े थे। राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर हार और जीत का अंतर का फासला 0.1 फीसदी से 8.5 फीसदी के बीच रहा था। यानि वोटों के प्रतिशत में थोड़ी सी हेरफेर रिजल्ट बदल सकता सकता है। साल 2019 के लोकसभा की तुलना में राज्य के सियासी समीकरण पूरी तरह से अलग हैं। बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है।

टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस-लेफ्ट और बीजेपी की लड़ाई है और बंगाल के चुनाव में जीत के लिए मुस्लिम फैक्टर काफी अहम है। क्योंकि इस समुदाय की आबादी 27 से 30 फीसदी की है। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत और लेफ्ट की पराजय के बाद अब तक इस समुदाय के वोट पूरी तरह से टीएमसी के खाते में जाते रहे हैं। लेकिन पिछले साल मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट सागरदिघी में हुए उपचुनाव में टीएमसी का उम्मीदवार पराजित हुआ था।

संदेशखाली- नौकरी में स्कैम बना मुद्दा : ऐसा माना जा रहा है कि संदेशखाली, नौकरी भर्ती में स्कैम और विकास जैसे मुद्दों को लेकर मुस्लिम समुदाय ममता बनर्जी से बहुत खुश नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस भी इस समुदाय के वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यदि मुस्लिम वोट बंटता है, तो इसका सीधा नुकसान टीएमसी को होगा और कहीं न कहीं बीजेपी को इससे लाभ मिलेगा।

दिल्ली कांग्रेस और ममता के सुर में नरमी : वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पार्थ मुखोपाध्याय का कहना है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के विभाजन को हर कीमत पर रोकना चाहती हैं। उत्तर बंगाल में मुस्लिम फैक्टर ज्यादा अहम नहीं था। इस कारण उन्होंने इस पर अपना पत्ता नहीं खोला था, लेकिन अब दक्षिण बंगाल में मुस्लिम वोटों के विभाजन से ममता को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना सुर बदल लिया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में वह बाहर से मदद करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि बंगाल में कांग्रेस और माकपा के खिलाफ उनकी लड़ाई है।

दल्लि के नेतृत्व और इंडिया गठबंधन से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। वह बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर चौधरी और माकपा पर जमकर हमला बोल रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेताओं को लेकर ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है। ऐसा नहीं है कि केवल ममता ने ही कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को लेकर चुप्पी साध रखी है। बंगाल में चार चरणों के मतदान हो चुके हैं। उन दोनों संसदीय सीटों पर भी मतदान हो गया है, जहां से कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी किसी ने भी बंगाल में एक भी रैली नहीं की है। सियासी संकेत साफ है कि कांग्रेस भी ममता बनर्जी को चुनाव के पहले नाराज नहीं करना चाहती है और चुनाव के बाद की संभावनाओं को जीवित रखना चाहती है। यही कारण है कि बंगाल की सियासी जंग कांग्रेस के अधीर चौधरी और ममता बनर्जी के बीच ही सिमट कर रह गई है।

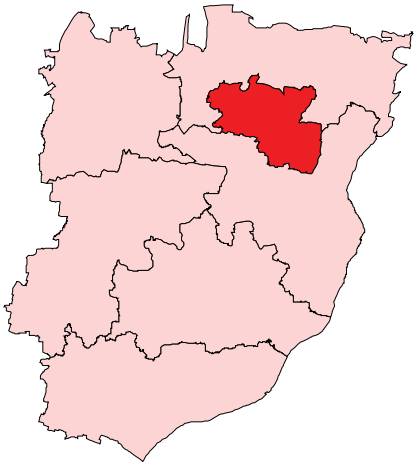

आरा लोस सीटः यादव-राजपूत वोटर्स तय करते हैं सांसद

*चंदन कुमार

आरा लोकसभा सीट की. यह बिहार की एक सबसे चर्चित सीट है. वर्तमान में यहां से केंद्र सरकार में मंत्री राजकुमार सिंह (आरके सिंह) सांसद हैं. एक बार फिर आरके सिंह तीसरी बार ताल ठोकने को तैयार हैं. आरा लोकसभा चुनाव अपने कई कारणों से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। भाजपा के उम्मीदवार की चुनौती यह होगी कि कैसे लगातार अपने प्रतिद्वंदी को लगातार तीन बार परास्त कर जीत का हैट्रिक बनाए। वहीं भाकपा माले के सामने चुनौती यह है कि हार के दस्तक को जीत में कैसे तब्दील करें। पिछले चुनाव में रनर रहे भाकपा माले इस बार उम्मीदवार बदल कर विनर बनने के युद्ध में शामिल हो गई है।

भाकपा माले के प्रत्याशी तरारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। माले के काफी सक्रिय सदस्य है और पार्टी में पदाधिकारी की भूमिका में भी रहे है। इन्हें गत लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 का अनुभव भी है। तब राजू यादव उम्मीदवार थे। इन्हें 4,19, 195 मत मिला था। राजू यादव ने माले के लिए एक बड़ी लकीर खींची थी। अब सुदामा प्रसाद को उस से भी बड़ी लकीर खींचनी है। इस बार ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इनके साथ वाम दल के अलावा राजद और कांग्रेस के भी कैडर का सहयोग मिलेगा। अब बात आरा लोकसभा क्षेत्र की जातीय समीकरण की. क्योंकि, बिहार में जातियों के बिना सियासत को समझना और उसकी कल्पना करना मुश्किल है. राज्य के बड़े से बड़े नेताओं ने किसी न किसी जाति के जरिए ही अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है. आरा लोकसभा की बात करें तो यहां कुल सात विधानसभा सीटें हैं. इसमें आरा, बड़हरा, संदेश, अगिआंव, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर शामिल हैं. आरा लोकसभा में कुल 21,56,048 लाख वोटर है जिसमें 11,45,328 पुरुष तथा 10,10,685 महिला मतदाता हैं. ट्रांसजेंडर की संख्या 35 हैं. **आरा के 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा** : आरा लोकसभा के अंदर सात विधान सभा क्षेत्र आते हैं। इनमे संदेश, बड़हरा, आरा, अगियांव, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर विधान सभा क्षेत्र आता है। इन सात विधानसभा सीटों में तीन राष्ट्रीय जनता दल के पास, दो भाजपा के पास और दो भाकपा माले के नाम है। यानी 5 विधानसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन के पास और दो विधान सभा एनडीए गठबंधन के पास है। राष्ट्रीय जनता दल के किरण यादव संदेश से विधायक हैं। जगदीशपुर विधान सभा से राजद के राम विष्णु सिंह के पास है। शाहपुर से राहुल तिवारी राजद के विधायक हैं। अंगियाव से माले के मनोज मंजिल विधायक थे। तरारी से स्वयं लोकसभा के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद विधायक हैं। दूसरी तरफ एनडीए के हिस्से में दो विधान सभा सीटें हैं। बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप,और आरा विधान सभा से अमरेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं।

आरा सीट से अगर भाकपा माले अपना प्रत्याशी उतारा है पिछड़ा, अतिपिछड़ा, मुसलमान समेत कुशवाहा समाज का वोट उसको मिल सकता है. जिले में पासवान जाति के मतदाताओं की संख्या 50 हजार के आसपास बताई जाती है. ये सीधे तौर पर लोजपा और भाजपा के साथ जुड़े हैं. यहां चंद्रवंशी समाज के वोटरों की संख्या भी 50 हजार के करीब है. इसमें ज्यादातर महागठबंधन के साथ हैं. बाकी अतिपिछड़ा वोट पांच लाख से ऊपर है. ये वोट सीधे तौर पर दोनों प्रत्याशियों के साथ है, लेकिन यहां भी भाजपा कुछ ज्यादा सेंधमारी कर सकती है.

जातीय समीकरण

यह लोकसभा सीट भोजपुर जिले के अंतर्गत आती है. यहां यादव, राजपूत, मुस्लिम, ब्राह्मण, पिछड़ा और अति पिछड़ा हर जाति और वर्ग का अपना वोट है. इन्हें कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती. भोजपुर जिले में यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है. जिले में लगभग 3 लाख 50 हजार यादव हैं. इन्हें आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है. हालांकि ये अब कुछ हद तक जेडीयू और बीजेपी में भी बंट सकते हैं. इन वोटों का कुछ प्रतिशत आरके सिंह के साथ जुट सकता है.

केजरीवाल का बड़ा दावा, चुनाव बाद योगी आदित्यनाथ से छिन सकती है कुर्सी

इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करने राजधानी लखनऊ पहुंचे आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर चुनाव बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का दावा किया। केजरीवाल और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक साझा प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है कि अमित शाह को अपना वारिस बनाएंगे और वह दो-तीन साल से इसमें लगे हुए हैं। इसमें जो भी नेता बाधा बन सकता था उन्हें एक-एक कर हटा दिया गया है जैसा शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा है जो इस राह में कांटा बन सकता है और वो योगी आदित्यनाथ हैं। केजरीवाल ने कहा कि योगी को हटाने का मन बना लिया है और यदि चुनाव जीतते हैं तो उन्हें कुछ ही महीनों में हटा दिया जाएगा।

दिल्ली के सीएम ने कहा कि भाजपा 400 पार सीटें चाहती है और उसके नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंदर से पता चला है कि भाजपा आरक्षण को खत्म करनी चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि संघ व भाजपा शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रहे हैं और ये संविधान को तार-तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वर्तमान सरकार के खिलाफ माहौल बन चुका है और उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में इनकी सीटें घट रही हैं। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चार चरणों में ही भाजपा पस्त हो गयी है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि देश की 140 करोड़ जनता भाजपा को 140 सीटें के नीचे पहुंचा देगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की 99 सीटों में ही उलझ कर रह गयी है जहां इसकी सबसे बड़ी हार होने वाली है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सपा मुखिया ने कहा कि इन्हें 400 पार सीटें आरक्षण और संविधान खत्म करने के लिए चाहिए। आप सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल पर दिल्ली सीएम के बंगले के बाहर हुए हमले के जवाब में कहा कि भाजपा इस पर राजनीतिक खेल न खेले। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जब पहलवान बेटियों के समर्थन में जंतर-मंतर पर गयी थी तो पुलिस ने उन्हें घसीट कर मारा था। प्रधानमंत्री और भाजपा को उस पर जवाब देना चाहिए।

दावों का आधार क्या

इस बार वक्त से पहले आ रहा मानसून

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के 31 मई को केरल में दस्तक देने की उम्मीद है। दक्षिण-पश्चिम मानसून आम तौर पर लगभग 7 दिनों के मानक अंतराल के साथ एक जून को केरल में प्रवेश करता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून आम तौर पर लगभग 7 दिनों के मानक समय के साथ एक जून को केरल में प्रवेश करता है; इसके बाद यह आमतौर पर मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून इस साल वक्त से पहले आ रहा है। आमतौर पर यह अंडमान-निकोबार द्वीप के तट पर 22 मई के आसपास दस्तक देता है लेकिन, इस बार यह तीन दिन पहले 19 मई तक पहुंच जाएगा। इस साल मानसून के 31 मई के आसपास केरल पहुंचने की उम्मीद है। मानसून के उत्तर की ओर बढ़ने पर चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं झारखंड में 13 से 17 जून के बीच मानसून आएगा।

अल-नीनो और ला-नीना का दिखेगा प्रभाव : मौसम विभाग के मुताबिक, अल नीनो प्रणाली के कमजोर पड़ने पर ला नीना की स्थितियां बेहतर हुई हैं। विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इसमें और सुधार होने की संभावना है। ला नीना के साथ-साथ हिंद महासागर द्विध्रुव स्थितियां भी इस साल अच्छे मानसून के लिए अनुकूल दिखाई दे रही हैं और ये सारे संकेत अच्छे मॉनसून की तरफ इशारा कर रहे हैं, इससे मई में सामान्य से अच्छी बारिश के अनुमान जताया गया है।

दक्षिण पश्चिम मानसून 19 मई को अंडमान सागर के साथ बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह पूर्वोत्तर भारत में 25 मई को आगे बढ़ेगा। उत्तर भारत में मानसून के 27 जून तक पहुंचने की उम्मीद है।इसके बाद 29 मई से 1 जून के बीच ये केरल में दस्तक दे सकता है। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री 10 जून को होगी तो वहीं 15 जून तक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में मानसून की एंट्री हो सकती है। 20 जून तक ये गुजरात और मध्य प्रदेश के आंतरिक इलाकों में दस्तक दे सकता है।इसके बाद मानसून 20 से 25 जून के बीच उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में भी एंट्री कर सकता है। 30 जून को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दस्तक दे सकता है और आगे बढ़ते हुए 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। हालांकि इसकी फिलहाल संभावना जताई गई है। दिल्ली में मानसून 28 से 30 जून तक पहुंचेगा तो वहीं मुंबई में 10 से 11 जून तक एंट्री लेगा, कोलकाता में भी 10 से 11 जून और चेन्नई में 10 जून तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने कहा कि पिछले 19 वर्षों के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत की तारीख के बारे में उसके परिचालन पूर्वानुमान 2015 को छोड़कर सही साबित हुए थे।

मंत्री आलमगीर के कहने पर वसूले थे पैसेः ईडी की पूछताछ में खुलासा, आलमगीर ने दिया इस्तीफा

टेंडर कमीशन घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। मंत्री के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर को जांच एजेंसी ने 6 मई को ही गिरफ्तार किया था। छापेमारी में जहांगीर के फ्लैट से 32.20 करोड़ कैश मिले थे। दोनों को रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रहा है। जहांगीर ने ईडी के समक्ष माना कि पैसे संजीव लाल के ही हैं। इसके बाद जब ईडी ने संजीव लाल से पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने इनकार किया। बाद में ईडी ने जब उसके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए तो उसने भी मान लिया कि जब्त 32.20 करोड़ रुपए टेंडर कमीशन के हैं और उसी के हैं।

संजीव लाल ने पूछताछ में बताया कि पैसे मंत्री आलमगीर के ही कहने पर वसूले थे। वह टेंडर कमीशन से मिले रुपए को छिपाकर रखता था। इसके लिए उसने अपने नौकर जहांगीर के नाम पर एक फ्लैट हरमू रोड में ले रखा था। पिछले तीन महीने से वह इस फ्लैट में कैश जमा कर रहा था। बता दें कि जिस इलाके में संजीव ने फ्लैट ले रखा था वहां के लोगों को कभी पैसे रखने की भनक तक नहीं लगी। टेंडर कमीशन घोटाला में ईडी एक बार फिर 6 मई से लगातार छापेमारी कर रहा है। अब तक हुई छापेमारी में ईडी ने 37.29 करोड़ रुपए जब्त किए हैं।

ईडी ने संजीव लाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट को जानकारी दी है कि टेंडर कमीशन से वसूली गई राशि विभागीय अधिकारियों में भी बंटती थी। कमीशन की राशि वसूलने के बाद संजीव की जिम्मेदारी थी कि उसे व्यवस्थित तरीके से सभी अधिकारियों के बीच बांटे। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है संजीव लाल के पास से जो दस्तावेज व डिजिटल डिवाइस मिले हैं, उसमें कई अहम जानकारी सामने आई हैं। कई अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जो इस टेंडर कमीशन में शामिल थे। सभी ईडी के रडार पर हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार में टॉप लेवल पर आलमगीर के इस्तीफे पर गहन मंथन भी शुरू हो गया है। लेकिन, अभी नतीजा नहीं निकला है। क्योंकि, हाल में चुनाव तक जमानत पर रिहा किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उसके बाद राजनीतिक खेमे में यह कहा जाने लगा है कि हेमंत ने इस्तीफा देकर भूल कर दी। अगर इस्तीफा नहीं देते तो संभव था कि केजरीवाल की तरह वह भी मुख्यमंत्री बने रहते। 2022 में महाराष्ट्र में एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक को भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया। जेल में रहते हुए भी मलिक ने भी इस्तीफा नहीं दिया था।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। यह ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल गेम है। पैसे की बरामदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस इसमें बीच में नहीं आएगी। लेकिन पैसा कहां बरामद हुआ, यह भी देखना चाहिए।

टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी अब तक 37.29 करोड़ जब्त कर चुका : टेंडर कमीशन घोटाला में ईडी एक बार फिर 6 मई से लगातार छापेमारी कर रहा है। अब तक हुई छापेमारी में ईडी ने 37.29 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसमें सबसे अधिक आलमगीर के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर के फ्लैट से 32.20 करोड़, संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के घर से 2.93 करोड़, उनके एक और करीबी ठेकेदार राजीव सिंह के ठिकाने से 2.14 करोड़, संजीव लाल के प्रोजेक्ट भवन स्थित चैंबर से 1.75 लाख व 28 हजार के पुराने नोट जब्त किए थे।

पंचायत चुनाव जीत राजनीति में आए थे आलमगीर

झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। जहां ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली है। आलमगीर आलम पर योजनाओं के बदले कमीशन लेने का आरोप है।

आलमगीर आलम साहिबगंज के रहने वाले हैं। चार बार विधायक रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आलमगीर आलम का जन्म साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के इस्लामपुर में हुआ। पिता सनाउल्लाह आलम जमींदार थे। गांव में उनकी पहचान सानू बाबू के नाम से थी। आलमगीर आलम पांच भाई हैं जिनमें आलमगीर दूसरे नंबर पर हैं। पिता से 55 बीघा जमीन हिस्से में मिली। आलमगीर ने कारोबार की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बरहरवा पहाड़ी बाबा चौक मस्जिद के पास ही एक दुकान खोली। जिसमें पंपिंग सेट मशीन, जनरेटर के अलावा स्पेयर्स पार्ट्स भी मिलता था। काफी लंबे समय तक आलमगीर इस व्यापार से जुड़े रहे। आलमगीर आलम की इलाके में अच्छी पकड़ थी। पिता के रास्ते पर चलते हुए आलमगीर ने 1978 में सरपंच का चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 1995 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का टिकट भी दिया लेकिन आलमगीर पहला चुनाव हार गए। साल 2000 में फिर कांग्रेस से मौका मिला तो चुनाव लड़े और इस बार जीत गए । धीरे-धीरे पार्टी में इनका कद बढ़ता गया और आज वो संसदीय कार्य मंत्री के साथ- साथ ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी हैं। अपने राजनीतिक जीवन में आलमगीर कई महत्वपूर्ण पद पर रहे।

पत्थर, कोयला के साथ-साथ कई कारोबार में है निवेशः आलमगीर राजनीति में आने के बावजूद भी कई व्यापार से जुड़े हैं। बरहरवा के मुगल पाड़ा के पास स्थित एक पेट्रोल पंप में उनके निवेश की चर्चा होती है। पश्चिम बंगाल के वर्दमान में राइस मिल है।

इसके अलावा आलमगीर आलम कोयला और पत्थर के कारोबार से भी जुड़े हैं। पत्थर व्यापारी आलम ब्रदर्स के महताब आलम के साथ पार्टनरशिप में वह कारोबार कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा स्थित कोल माइंस से भी रोजाना 10 से 15 ट्रक कोयले की सप्लाई में भी उनकी हिस्सेदारी है जिसे उनका बेटा तनवीर आलम देखता है। इसके अलावा रांची में पानी सप्लाई के कारोबार से भी आलमगीर जुड़े हैं।

धर्म को बहाना बनाकर ध्रुवीकरण बढ़ाने वाले भाषण

▪ चारु कार्तिकेय

चुनावों के दौरान धर्म को बहाना बनाकर ध्रुवीकरण बढ़ाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या की बात कम हो रही है. ये साल करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं. आखिर कैसे मिलेगा इन्हें रोजगार?

लोकसभा चुनावों में जैसे-जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है पार्टियों के चुनावी अभियान और भड़काऊ होते जा रहे हैं. ऐसे में बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है.

रोजगार रहित आर्थिक विकास यानी 'जॉबलेस ग्रोथ' से पिछली सरकारें भी जूझती रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विशेष आरोप यह है कि उसके कार्यकाल में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई जितनी बीते चार दशकों में नहीं बढ़ी थी.

यह बात सरकारी आंकड़े 2019 में ही दिखा रहे थे. फरवरी, 2019 में 'बिजनेस स्टैंडर्ड' अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक सरकारी सर्वेक्षण में पाया गया कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर थी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया.

आखिरकार मई, 2019 में सरकार को इन आंकड़ों को सार्वजनिक करना ही पड़ा. आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत थी, जो 45 सालों में सबसे ऊंचा स्तर था. इस रिपोर्ट को आए पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति नाजुक ही बनी हुई है.

ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्तूबर से दिसंबर, 2023 के बीच देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत थी. निजी संस्थानों का आकलन इससे ज्यादा गंभीर है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के मुताबिक फरवरी, 2024 में कुल बेरोजगारी दर आठ प्रतिशत हो गई थी.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इकनोमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के प्रोफेसर प्रवीण झा कहते हैं, "बेरोजगारी वाकई में एक बड़ी समस्या है. सर्वसम्मत राय यह है कि कुल मिलाकर रोजगार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है."

कई जानकारों का कहना है कि उन्हें विशेष रूप से युवा बेरोजगारी के बढ़ने की विशेष रूप से चिंता है. सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि 2022-23 में 15-29 साल के युवाओं में से लगभग 16 प्रतिशत युवा कौशल की कमी और अच्छी नौकरियों की भी कमी की वजह से बेरोजगार रह गए.

निजी संस्थाओं का मानना है कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा खराब है. सीएमआईई के मुताबिक युवा बेरोजगारी दर 45.4 प्रतिशत है. हाल ही में जारी की गई एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर तीसरा युवा ना तो पढ़ाई कर रहा है, ना ही नौकरी और ना ही कोई प्रशिक्षण हासिल कर रहा है.

यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने नई दिल्ली स्थित थिंक-टैंक इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (आईएचडी) के साथ मिलकर जारी की थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अशिक्षित युवाओं के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना और कम है.

जहां अशिक्षित युवाओं में 3.4 प्रतिशत बेरोजगारी दर पाई गई, वहीं ग्रेजुएट युवाओं में यह दर 29.1 प्रतिशत पाई गई. माध्यमिक या उच्च शिक्षा पा चुके युवाओं में बेरोजगारी दर 18.4 पाई है.

आईएचडी के सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव ने इस रिपोर्ट को बनाने वाली की टीम का नेतृत्व किया था. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि युवा बेरोजगारी देश की बेरोजगारी समस्या के केंद्र में है.

उन्होंने कहा, "बाकी सब अंडरएम्प्लॉयमेंट है, या जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन या तो उन्हें बहुत कम वेतन मिल रहा है या वो बहुत कम दिनों के लिए काम कर पा रहे हैं. लेकिन जहां तक 'ओपन अनएम्प्लॉयमेंट' का सवाल है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा युवा बेरोजगारी से ही बनता है."

हर साल करोड़ों युवा रोजगार के बाजार में कदम रखते हैं. ऐसे में अच्छी नौकरियों की कमी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. देश की आबादी में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी को जनसांख्यिकीय लाभांश या 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' माना जाता है, लेकिन जानकार चेताते हैं कि बेरोजगारी इस युवा शक्ति को एक बोझ में बदल सकती है.

अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि उनके और उनके साथियों का अनुमान है कि देश में पहले से करीब 28 करोड़ नौकरियों की कमी है और उसमें हर साल रोजगार के बाजार में कदम रखने वाले करीब 2.4 करोड़ युवा जुड़ते हैं.

कुमार ने यह भी बताया, "इसके विपरीत हर साल संगठित क्षेत्र में सिर्फ करीब पांच लाख नौकरियों का ही सृजन हो पाता है, जबकि बाकी सारी नौकरियां असंगठित क्षेत्र में हैं, जैसे किसी ने पकोड़े तल लिए, किसी ने सब्जी बेच ली, मूंगफली बेच ली, रिक्शा चला लिया, माल ढो लिया आदि."

ऐसे हालात में क्या इतनी भीषण गर्मी में अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक जाने वाले लोगों के मन में बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं है? अप्रैल में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 62 प्रतिशत लोगों ने कहा कि नौकरी ढूंढना पहले के मुकाबले आज ज्यादा मुश्किल है.

27 प्रतिशत लोगों ने यह भी कहा कि चुनावों में किसे वोट देना है यह तय करने के लिए उनके सामने बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण विषय है. हालांकि बीजेपी चुनावों के दौरान इस विषय से कतरा रही है.

विपक्षी पार्टियों का 'इंडिया' गठबंधन बेरोजगारी और अन्य आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मतदाताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मतदाता किसकी सुनते हैं यह जानने के लिए दोनों ही पक्षों को चार जून का इंतजार रहेगा.

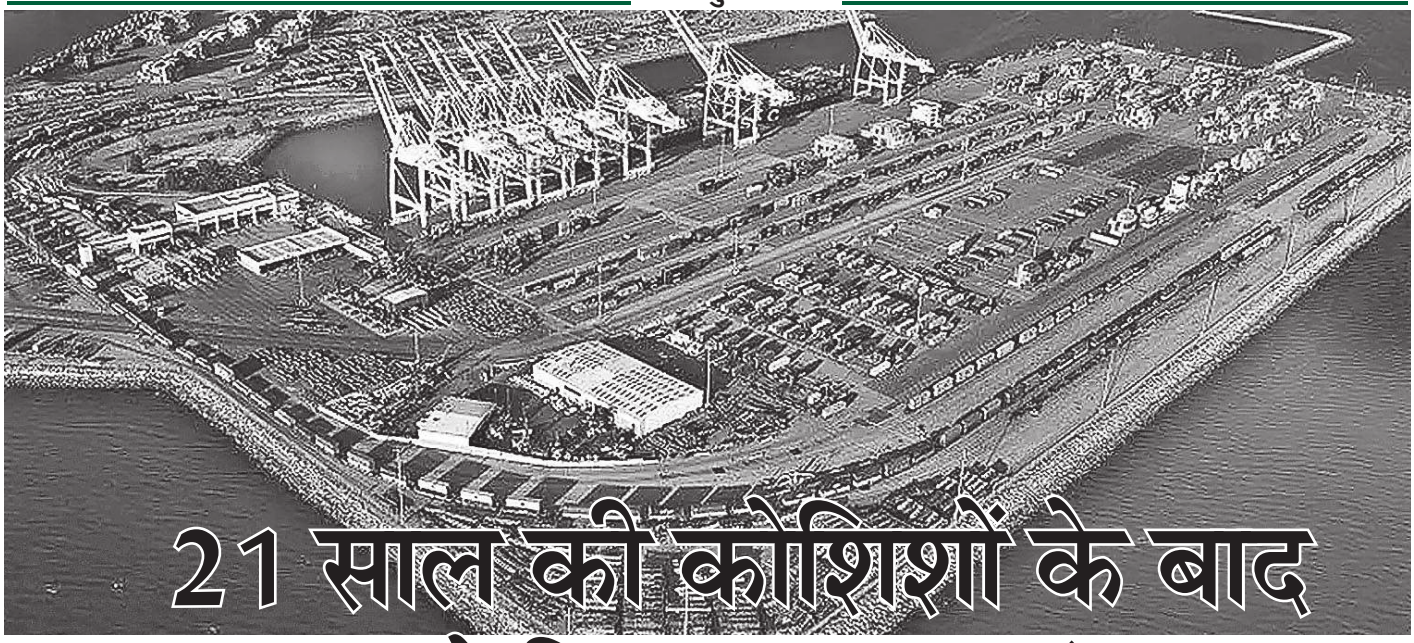

21 साल की कोशिशों के बाद भारत को मिला चाबहार बंदरगाह

ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह के विकास और प्रबंधन को लेकर समझौता हो गया है. इस समझौते के लिए बातचीत 2003 में शुरू हुई थी.

भारत को ईरान का चाबहार बंदरगाह के 10 साल तक इस्तेमाल के अधिकार मिल गए हैं. भारत इस बंदरगाह का विकास करेगा और 10 साल तक इसका प्रबंधन करेगा. पाकिस्तान से लगती ईरान की दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर स्थित चाबहार बंदरगाह को समुद्री व्यापार के लिए एक अहम और रणनीतिक जगह माना जाता है.

ईरान के शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि समझौते के तहत भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) कंपनी चाबहार में 37 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी और "बंदरगाह का ढांचागत विकास" करने के लिए "रणनीतिक उपकरण" उपलब्ध कराएगी.

भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश ने समझौते पर दस्तखत किए.

बजरपाश ने इस मौके पर कहा, "इलाके में परिवहन के विकास में चाबहार एक अहम केंद्र बन सकता है. हम इस समझौते से बेहद खुश हैं और भारत पर हमें पूरा भरोसा है."

सोनोवाल ने कहा कि भारत और ईरान "क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच के दोनों देशों के हितों को देखते हुए चाबहार बंदरगाह के हरसंभव विकास को लेकर" बहुत उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, "लंबी अवधि का यह समझौता भारत और ईरान के बीच सदा से रहे भरोसे और प्रभावशाली साझेदारी का प्रतीक है.

इस समझौते पर भारत और ईरान के बीच लगभग 20 साल से बातचीत चल रही थी. 2003 में भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह के विकास में हिस्सेदारी पर बातचीत शुरू की थी. अगस्त 2012 में इस समझौते को लेकर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई जिसके बाद जनवरी 2013 में भारत ने चाबहार में 10 करोड़ डॉलर के निवेश पर सहमति दी थी.

2016 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए 50 करोड़ डॉलर उपलब्ध कराने पर सहमति दी थी. तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी की मौजूदगी में सहमति पत्र पर दस्तखत भी हो गए थे.

> ईरान के शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि समझौते के तहत भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) कंपनी चाबहार में 37 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी और "बंदरगाह का ढांचागत विकास" करने के लिए "रणनीतिक उपकरण" उपलब्ध कराएगी.

लेकिन यह समझौता सिरे नहीं चढ़ पाया क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच 2015 में हुआ ऐतिहासिक परमाणु समझौता 2018 में डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद टूट गया और अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए.

अमेरिका नाखुश : अमेरिका इस समझौते को लेकर बहुत खुश नहीं रहा है लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद उसने इसे स्वीकार कर लिया था. हालांकि सोमवार को उसने चेतावनी दी कि भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

अमेरिका ने एक बार फिर इस समझौते को लेकर कड़ा रुख दिखाया. वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चाबहार में काम करने वाली कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, "चूंकि यह अमेरिका से जुड़ा मामला है, इसलिए ईरान पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे. ईरान के साथ व्यापार करने वाली हर कंपनी को, चाहे वह कहीं की भी हो, इस बात का पता होना चाहिए वह प्रतिबंधों का खतरा मोल ले रही है."

क्यों अहम है चाबहार?

चाबहार एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है. यह मध्य और पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान के व्यापार का अहम मार्ग बन सकता है. चाबहार बंदरगाह असल में दो अलग बंदरगाहों से मिलकर बना है. इन्हें 'शाहिद कलंतरी' और 'शाहिद बेहेस्ती' कहा जाता है. भारतीय कंपनी 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह का विकास करेगी. इसके जरिए भारत का अफगानिस्तान से सीधा रास्ता खुल जाएगा और उसे पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना होगा. अभी भारत को यदि अफगानिस्तान सामान भेजना हो तो उसके ट्रकों को पाकिस्तान होकर जाना पड़ता है. दोनों देशों के बीच तनाव अक्सर इसमें बाधा बनता है. चाबहार बंदरगाह का फायदा अफगानिस्तान को भी होगा और उसकी पाकिस्तान पर निर्भरता कम होगी. इससे अफगानिस्तान की राजनीति पर पाकिस्तान का प्रभाव कम होगा, जिसका रणनीतिक फायदा भारत को मिल सकता है. चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर स्थित है. ग्वादर पाकिस्तान का वह बंदरगाह है जिसे चीन विकसित कर रहा है. इसके जरिए चीन अरब सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है.

गाजा में युद्ध पर बाइडेन व नेतन्याहू में बढ़ता तनाव

हमास से लड़ाई के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति और इस्राएली प्रधानमंत्री के रिश्तों में खटास बढ़ गई है. एक माह से ज्यादा समय तक दोनों में बोलचाल बंद थी. अब बातचीत हो रही है तो उसमें कड़वाहट और धमकियों के सुर गूंज रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने जटिल रिश्तों को लंबे समय से बचा रखा है, हालांकि गाजा युद्ध पर उनकी सोच में फर्क, उनके लिए एक दूसरे को असहनीय बना रहा है. इसकी एक वजह दोनों ही नेताओं के राजनीतिक भविष्य का अधर में लटका होना भी है.

पिछले दिनों बाइडेन ने इस्राएल को भारी बमों की आपूर्ति रोक दी. इसके साथ चेतावनी दी कि अमेरिका टैंक के लिए गोला बारूद और दूसरे हथियारों को भेजना भी रोक सकता है, अगर इस्राएल गाजा के रफाह में बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई शुरू करता है.

नेतन्याहू ने बाइडेन की चेतावनियों को कंधे उचका कर झाड़ दिया और खम ठोक कर कहा, "अगर हमें अकेले खड़ा होना पड़ा तो हम अकेले ही डट जाएंगे. अगर हमें जरूरत पड़ी तो अपने नाखूनों के सहारे लड़ेंगे लेकिन हमारे पास नाखूनों से बहुत कुछ ज्यादा है."

बाइडेन को लंबे समय तक इस बात पर गर्व रहा है, कि वह नेतन्याहू को सजा की बजाय इनामों से संभालते आए हैं. हालांकि पिछले सात महीनों में जिस तरह दोनों में टकराव बढ़ा है, उससे लगता है कि यह बीते दिनों की बात हो गई. दोनों नेता मध्य पूर्व की विस्फोटक स्थिति से घरेलू राजनीतिक समस्याओं को भी संतुलित करने की कोशिश में हैं. बाइडेन के सार्वजनिक हमलों और निजी अनुरोधों के सामने नेतन्याहू का रवैया तेजी से प्रतिरोध की ओर बढ़ रहा है.

इसके नतीजे में बाइडेन और ज्यादा दृढ़ हुए हैं. बाइडेन ने अमेरिकी टीवी चैनल सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "अगर वे रफाह जाते हैं, तो मैं उन्हें वो हथियार नहीं दूंगा जिनका इस्तेमाल पहले से रफाह में होता रहा है, शहरों और समस्याओं से वो निपटें." बाइडेन के सहयोगी अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में अमेरिका-इस्राएल के संबंधों को बिगड़ते नहीं देखना चाहते. वो सिर्फ राजनीति का जिक्र नहीं करते, ज्यादातर अमेरिकी इस्राएल का समर्थन करते हैं, साथ ही बाइडेन का निजी इतिहास इस्राएल के साथ रहा है, और वो उसके आत्मरक्षा के अधिकार में यकीन रखते हैं.

राष्ट्रपति के सहयोगी यह देख रहे हैं कि कैसे फलीस्तीन समर्थक प्रदर्शनों ने उनकी पार्टी और कॉलेज परिसरों को अपने घेरे में ले लिया है, जो डेमोक्रेटिक वोटरों के लिए कभी जमीन तैयार करती थी. कई महीनों से ऐसा लग रहा है कि कहीं बाइडेन, व्हाइट हाउस में पहुंचने वाले आखिरी इस्राएल समर्थक नेता ना बन जाएं. नेतन्याहू को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को लेकर लोगों की उम्मीदें उसी विवादित घेरे में फंस रही हैं जिसमें इस्राएल से उलझने वाले कई अमेरिकी राष्ट्रपति बीते दशकों में फंसते आए हैं.

बाइडेन और नेतन्याहू एक दूसरे को तब से जानते हैं जब बाइडेन एक युवा सीनेटर और नेतन्याहू इस्राएली दूतावास में वरिष्ठ अधिकारी थे. उनके बीच पहले भी टकराव हो चुके हैं. बराक ओबामा के दौर में बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहते, पश्चिमी तट पर इस्राएली बस्तियों को लेकर भी उनमें विवाद हुआ था. बाद में नेतन्याहू ने ईरान के साथ परमाणु करार को फिर से बहाल करने का भी जम कर विरोध किया. यह करार ओबामा के शासन काल में हुआ था जिसे डॉनल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया.

2021 में इस्राएल की हमास के साथ 11 दिन चली जंग को शांत करने के लिए जब बाइडेन ने उन पर दबाव डाला तब भी वह बहुत झल्लाए थे. गाजा में बढ़ते मानवीय संकट की वजह से ही बाइडेन की निराशा बढ़ने लगी और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच इस साल एक महीने से ज्यादा बातचीत बंद थी. इन विवादों के बावजूद मध्य वामपंथी डेमोक्रेट नेता और इस्राएल के सर्वकालिक धुर दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार के प्रमुख के बीच रिश्ता बना रहा. हालांकि यह अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, जिसमें यह कहना मुश्किल है कि ये दोनों उसे कैसे आगे ले जाएंगे.

नेतन्याहू पर बंधकों को छुड़ाने के लिए सार्वजनिक दबाव है. दूसरी तरफ उनके गठबंधन के कट्टरपंथी चाहते हैं कि वह अपने हमले का विस्तार कर उसे रफाह तक ले जाएं. रफाह में करीब 13 लाख फलीस्तीनियों ने शरण ले रखी है. अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वह रफाह अभियान को आगे बढ़ाएंगे चाहे बंधकों के लिए करार हो या न हो. इस्राएली नेता ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास को ध्वस्त करने की शपथ ली है. हमास के आकस्मिक हमले में 1,200 इस्राएली लोगों की मौत हुई और करीब 250 लोगों को बंधक बनाया गया.

हालांकि नेतन्याहू के लिए लोगों का समर्थन उसके बाद से लगातार घट रहा है. अब उन पर दबाव है कि वह युद्ध रोक कर ऐसा समाधान निकालें, जिससे कि बंधकों और मारे गए इस्राएलियों के अंतिम अवशेषों को सुरक्षित वापस लाया जा सके. नेतन्याहू ने हमास के हमले के बारे में खुफिया और सैन्य नाकामी की जांच कराने से इनकार किया है. सारी घटनाओं के बीच उनके खिलाफ कानूनी समस्याएं बनी हुई हैं. इनमें लंबे समय से चल रहा भ्रष्टाचार का एक मुकदमा भी है, जो उनके खिलाफ धोखाधड़ी और घूस लेने के आरोपों से जुड़ा है.

नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य रफाह पर हमले से जुड़ा हुआ है. अगर वह बंधकों के लिए करार कर लेते हैं, और रफाह पर हमला रोक देते हैं, तो गठबंधन के कट्टरपंथी उनकी सरकार गिराने और नया चुनाव कराने की धमकी दे रहे हैं. दूसरी तरफ ओपिनियन पोल इस समय चुनाव में उनकी हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं. नेतन्याहू की जीवनी लिखने वाले स्तंभकार आंशेल फेफर ने एक इस्राएली अखबार में लिखा है, "अपने सहयोगियों को साथ रखने और समय से पहले चुनाव रोकने के लिए, जिसमें लिकुड का पतन होगा और उनका पद छिन जाएगा, उन्हें 'संपूर्ण विजय' के मिथक को जीवित रखना होगा, और यह सिर्फ तभी संभव है, जब हमास से समझौता ना हो."

नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता और चीफ ऑफ स्टाफ आविव बुशिंस्की का कहना है कि इस्राएली नेता का ध्यान पूरी तरह युद्ध के प्राथमिक उद्देश्य, हमास को हराने पर है, क्योंकि उन्हें अपनी छवि और विरासत की चिंता है. नेतन्याहू ने अपने पूरे करियर में खुद को "आतंक पर कठोर शख्स" के रूप में दिखाया है. बुशिंस्की कहते हैं, "वह समझते हैं कि इसी तरह से उन्हें याद रखा जाएगा. वह एक दशक से हमास को मसलने का वादा करते रहे हैं. उन्हें लगता है कि अगर वह ऐसा नहीं कर सके तो उन्हें सबसे बुरे प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाएगा."

उधर अमेरिका में इस वक्त बाइडेन युवा अमेरिकियों के विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं. यह उनके वोटरों का वह धड़ा है जो दोबारा चुने जाने में अहम भूमिका निभाएगा. इसके अलावा उन्हें अमेरिकी मुसलमानों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है जो मिशिगन में प्रमुख स्थिति में हैं. कुछ ने तो उन्हें युद्ध को संभालने में उनकी भूमिका पर विरोध जताने के लिए नवंबर में वोट नहीं देने की धमकी देनी भी शुरू कर दी है.

बाइडेन के सहयोगी बर्नी सांडर्स भी युद्ध पर प्रशासन के रवैये से परेशान हैं. सांडर्स का कहना है कि बाइडेन को आगे बढ़ कर इस्राएल को सभी हमलावर हथियारों की आपूर्ति रोक देनी चाहिए. सांडर्स ने कहा है, " निश्चित रूप से हमें अपनी स्थिति का पूरा फायदा उठा कर गाजा की तबाही को और ज्यादा बढ़ने से रोकना चाहिए." सांडर्स का यह भी कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगियों का साथ देता है और देना भी चाहिए, लेकिन सहयोगियों को भी अमेरिकी मूल्यों और कानूनों के साथ खड़ा होना चाहिए.

इसी दौर में बाइडेन को रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना भी झेलनी पड़ रही है. पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का कहना है, "इस्राएल के संदर्भ में जो बाइडेन कर रहे हैं वह अपमानजनक है. अगर किसी यहूदी ने जो बाइडेन को वोट दिया है तो वह खुद पर शर्मिंदा होगा. उन्होंने इस्राएल को छोड़ दिया है."

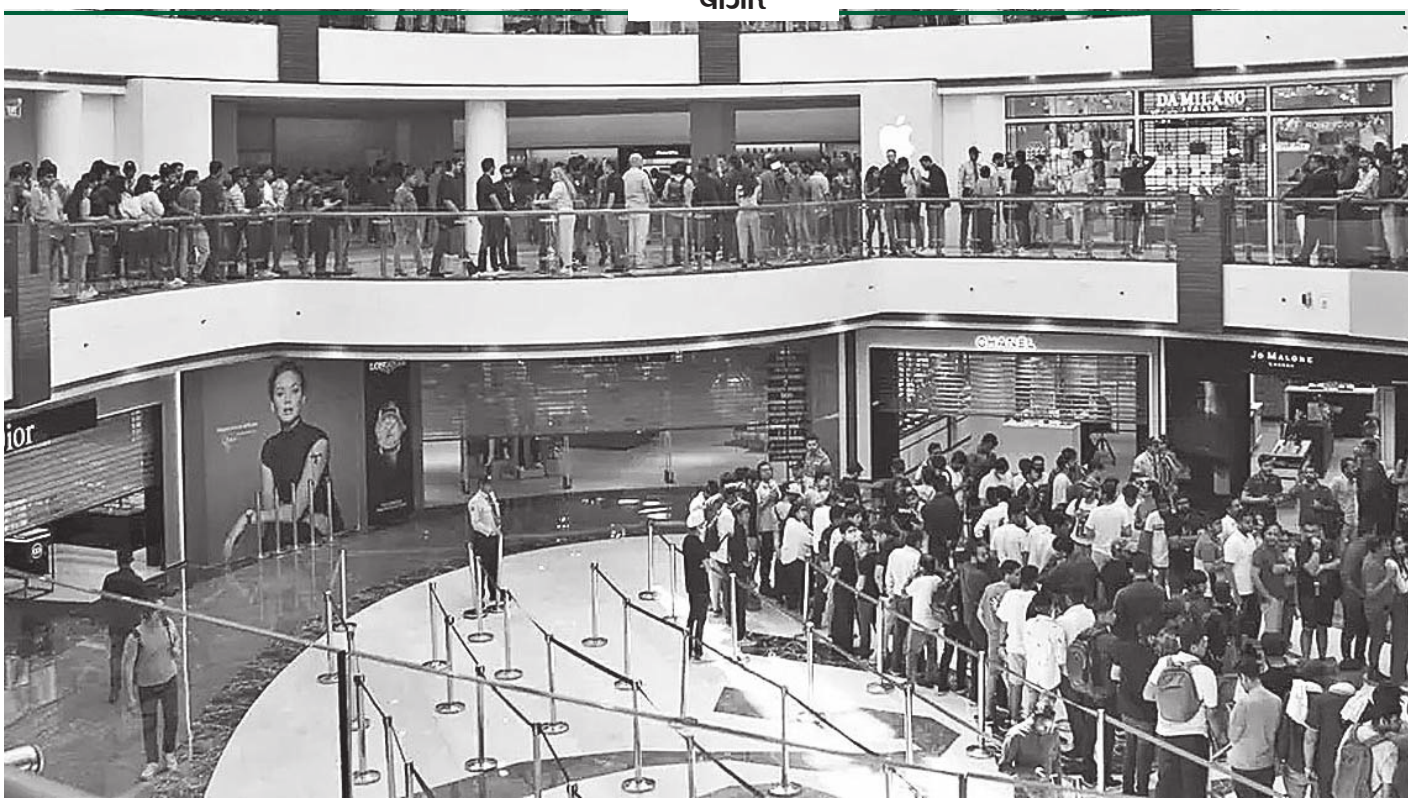

भारत में तेजी से बंद हो रहे हैं छोटे शॉपिंग मॉल

एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में शॉपिंग मॉल बुरे दौर से गुजर रहे हैं. पिछले दो साल में बहुत से छोटे शॉपिंग माल बंद हो गए.

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में छोटे शॉपिंग मॉल तेजी से बंद हो रहे हैं क्योंकि ग्राहक अब या तो ऑनलाइन खरीददारी कर रहे हैं या फिर बड़े मॉल जाना पसंद करते हैं.

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट एंड फ्रैंकलिन ने यह रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया कि मॉल के अंदर दुकानों के खाली होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है. जब किसी मॉल में 40 फीसदी से ज्यादा दुकानें खाली हो जाती हैं तो उसे 'घोस्ट मॉल' यानी नाकाम करार कर दिया जाता है.

रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भारत में ग्रॉस लीजेबल एरिया यानी किराये के लिए तैयार दुकानों की संख्या 238 फीसदी बढ़ी है लेकिन 2022 में घोस्ट मॉल 57 से बढ़कर 64 हो गए.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्राहकों में मांग की कमी का संकेत है जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का कारण बन सकती है. इसका असर छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है.

भारत के जीडीपी में निजी उपभोग की हिस्सेदारी 60 फीसदी है. लेकिन इसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है. 2023 की आखिरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की दर से बढ़ी लेकिन निजी उपभोग में सिर्फ 3.5 फीसदी की वृद्धि हुई.

> 29 शहरों के सर्वे पर आधारित नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट 'थिंक इंडिया थिंक रीटेल 2024' शीर्षक से जारी की गई है. फर्म के निदेशक गुलाम जिया ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "बहुत सारे छोटे शॉपिंग मॉल बंद होने के कगार पर हैं."

29 शहरों के सर्वे पर आधारित नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट 'थिंक इंडिया थिंक रीटेल 2024' शीर्षक से जारी की गई है. फर्म के निदेशक गुलाम जिया ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "बहुत सारे छोटे शॉपिंग मॉल बंद होने के कगार पर हैं."

एक लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले 132 शॉपिंग मॉल नाकाम होने के कगार पर हैं. 2022 में इनमें खाली पड़ी दुकानों की संख्या 33.5 फीसदी थी जो 2023 में बढ़कर 36.2 फीसदी हो गई.

रिपोर्ट में बताया गया है कि कमर्शियल रीटेल प्रॉपर्टी का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. 2023 में 133 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल की दुकानें खाली पड़ी थीं जिस कारण डिवेलपर्स को 67 अरब रुपये का नुकसान हुआ.

जिया कहते हैं कि छोटे शॉपिंग मॉल इसलिए नाकाम हो रहे हैं क्योंकि वे बड़े शॉपिंग सेंटरों जैसी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं. इस कारण उनके मालिक गिरावट झेल रहे हैं.

बड़े शॉपिंग मॉल, यानी ऐसे बाजार जिनका क्षेत्रफल पांच लाख वर्ग फुट से ज्यादा है, ज्यादा परेशानी में नहीं दिखाई देते. वहां खाली दुकानों की संख्या पांच फीसदी पर ही बनी हुई है. मध्यम आकार वाले शॉपिंग मॉल में यह दर 15.5 फीसदी है.

2023 में भारत में 12.5 करोड़ वर्गफुट में फैले मॉल 'घोस्ट मॉल' की श्रेणी में थे. इनमें से 75 फीसदी आठ सबसे बड़े शहरों में थे. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत देश के आठ सबसे बड़े शहरों में 2023 में कुल शॉपिंग मॉल घटकर 263 रह गए. हालांकि इन शहरों में आठ नए सेंटर खुले लेकिन 16 बंद हो गए. बंद होने वाले मॉल सबसे ज्यादा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में थे, 53 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैली दुकानें बंद हुईं जो 2022 के मुकाबले 58 फीसदी ज्यादा था.

मुंबई में 21 लाख वर्ग फुट और बेंगलुरु में 20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में मॉल बंद हुए. लेकिन 2022 के मुकाबले इन शहरों में बंद हुए मॉल की यह दर क्रमशः 86 फीसदी और 46 फीसदी थी. हैदराबाद में 19 फीसदी कम क्षेत्रफल में दुकानें बंद हुईं. यानी वहां दुकानें बंद होने की संख्या घटी है.

अब चीन से ज्यादा भारत के छात्र पढ़ने आ रहे हैं जर्मनी

*निखिल रंजन

कई सालों तक पढ़ाई के लिए जर्मनी आने वाले छात्रों में सबसे बड़ी संख्या चीनियों की होती थी. अब भारतीय छात्र उनसे आगे निकल गए हैं. बीते 4-5 सालों में यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है. भारतीय छात्रों का रुझान हमेशा से अंग्रेजी-भाषी देशों की तरफ ज्यादा रहा है. उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उनके पसंदीदा ठिकाने रहे हैं. हालांकि इन देशों में ऊंची फीस और बाकी खर्च ज्यादा होने के साथ ही वीजा मिलने की दिक्कत उन्हें हतोत्साहित भी करती है. इन सब के बीच जर्मनी की ओर भारतीय छात्रों का आकर्षण बढ़ा है. सिर्फ पांच साल के अंतराल में ही यहां पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है. जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) के मुताबिक, 2022 में भारत से जर्मनी आने वाले छात्रों की संख्या 42, 997 तक पहुंच गई जो बीते कई वर्षों में सबसे ज्यादा है. एक साल पहले से ही अगर तुलना करें तो यह करीब 26 फीसदी ज्यादा है. 2021 में 34,134 छात्रों ने जर्मनी का रुख किया था.

आंकड़े बताते हैं कि 2018 में 20,810 छात्र थे जो 2022 तक 43,000 के करीब पहुंच गए यानी लगभग दोगुने से भी ज्यादा. इनमें 70 फीसदी लड़के और 30 फीसदी लड़कियां हैं. ज्यादातर भारतीय छात्र तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं. लगभग 60 फीसदी छात्रों ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया जबकि कानून, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान में 22 फीसदी छात्रों ने रुचि दिखाई. 14 फीसदी छात्रों ने गणित और प्राकृतिक विज्ञान को चुना.

कई सालों से जर्मनी आने वाले छात्रों में सबसे बड़ी संख्या चीनी स्टूडेंट्स की होती थी. 2022 में यह संख्या 39,132 रही और भारतीय छात्र संख्या बल में उनसे आगे निकल गए. भारतीय छात्रों का समुदाय अब जर्मनी में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुदाय है.

बॉन यूनिवर्सिटी से न्यूरोसाइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने झारखंड के रांची से जर्मनी आईं निहारिका कश्यप बताती हैं कि उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी उनकी पहली पसंद था. उन्होंने इसकी कई वजहें बताईं, "विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में रिसर्च करने वालों के लिए मेरी ही क्या पूरी दुनिया की पहली पसंद जर्मनी है." इसका श्रेय वह जर्मन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई और रिसर्च के उच्च स्तर को देती हैं.

विदेशी छात्रों की जर्मनी में दिलचस्पी बढ़ने के कई कारण है. यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में रोजगार के भी पर्याप्त मौके मौजूद हैं. वास्तव में यहां कुशल कामगारों की भारी कमी है. बहुत से छात्र पढ़ाई के बाद उसी देश में नौकरी भी चाहते हैं, और इस लिहाज से जर्मनी आना बहुत फायदेमंद रहता है.

इसके अलावा जर्मनी की ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में ट्यूशन फी या तो होती नहीं या फिर बहुत मामूली होती है. ऐसे में छात्रों को सिर्फ अपने खर्चों के लिए ही पैसे की जरूरत पड़ती है. कश्यप ने बताया, "एक साल पढ़ाई का खर्च यहां लगभग 11 लाख रुपये है जिसमें सेमेस्टर फी के नाम पर पूरे दो साल में सिर्फ 127,000 रुपये ही देने हैं. बाकी का पैसा रहने खाने का खर्च है."

छात्रों को यहां पढ़ाई के दौरान हफ्ते में 8-20 घंटे तक काम करने की भी छूट मिलती है. इसलिए वह अपने जेब खर्च या फिर दूसरी चीजों के लिए कुछ पैसा भी आसानी से कमा लेते हैं.

जर्मनी ने वीजा नियमों में कई सुधार कर छात्रों के लिए यहां आना आसान बनाया है. अब तो कई भारतीय डिग्रियों को मान्यता मिलने लगी है और उनकी पहले से जांच कराना भी जरूरी नहीं रह गया है. इसके अलावा वीजा की शर्तें भी आसान बनाई गई हैं. छात्रों को पढ़ाई के बाद नौकरी खोजने के लिए भी वीजा मिल रहा है. यानी पढ़ाई पूरी होने पर तुरंत नौकरी नहीं मिली तो भी छात्र कुछ समय तक यहां रह कर नौकरी खोज सकते हैं.

जर्मन सांख्यिकी विभाग के आंकड़े दिखाते हैं कि 2012 से 2017 के बीच रेजिडेंस परमिट हासिल करने वाले लोगों में से 83 फीसदी ने पांच साल की अवधि बीत जाने के बाद भी जर्मनी में ही रुकने का फैसला किया. इन पांच सालों के दौरान 68,900 लोगों को जर्मनी में ब्लू कार्ड मिला. इनमें सबसे ज्यादा यानी 22.4 फीसदी लोग भारतीय थे. चीन का हिस्सा इनमें 8.7 फीसदी जबकि रूस का 7.5 फीसदी था. दूसरे देश से आ कर जर्मनी रह जाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या पूर्व अंतरराष्ट्रीय छात्रों की है. 55 फीसदी छात्र पांच साल का रेजिडेंट परमिट खत्म हो जाने के बाद भी जर्मनी में ही रुक जाते हैं. हालांकि जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बीते दस सालों में 19.6 फीसदी घटी है.

भारतीय छात्रों का जर्मनी आना बढ़ा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं. जर्मन भाषा की मुश्किल आज भी उनके लिए सबसे बड़ी है. जो छात्र पहले से जर्मन भाषा नहीं जानते उन्हें यहां कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ता है.

निहारिका कश्यप ने कहा, "बहुभाषी देश से आने के बावजूद जर्मनी में भाषा की वजह से रोजमर्रा के कामों में बड़ी दिक्कत होती है. यह मुश्किल एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही शुरू हो जाती है. डॉक्टर की सलाह से लेकर बस स्टॉप का नाम सुनने और बोलने में बड़ी परेशानी होती है. राशन खरीदना, या किसी से कुछ पूछना भी मुश्किल ही है. अंग्रेजी भाषी देशों में कम से कम यह दिक्कत नहीं है."

बहुत से कोर्सों में दाखिले के लिए जर्मन भाषा का ज्ञान जरूरी है. हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर बहुत सारे कोर्स अब अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी किए जा सकते हैं. जर्मनी छात्रों को जर्मनी आ कर भाषा सीखने के लिए भी वीजा देता है जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है.

बीते कुछ वर्षों में छात्रों को किराये पर घर लेने और इस तरह की दूसरी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है. इसके अलावा यहां मनपसंद भोजन का नहीं मिलना और घर के सारे काम खुद करने की दिक्कत भी है. भारत से आने वाले छात्र यह देख कर हैरान रह जाते हैं कि यहां घर साफ करने से लेकर कपड़े धोने और खाना बनाने या बाजार से खरीदारी तक का सारा काम खुद करना होता है.

भारत के सामान्य मध्यवर्गीय परिवारों में इसकी जरूरत आमतौर पर कम लोगों को पड़ती है. हालांकि यह छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी करता है. कश्यप कहती हैं यह मुश्किल तो भारत के बाहर सभी देशों में है, जर्मनी ही अकेला ऐसा नहीं है.

जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का निधन, ईडी ने किया था पिछले साल गिरफ्तार

बंद पड़ी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं। नरेश गोयल को हाल में अंतरिम जमानत दी गई थी और अंतिम समय में अपनी पत्नी के साथ थे। सूत्रों के मुताबिक अनीता गोयल ने तड़के तीन बजे अंतिम सांस ली। नरेश गोयल भी कैंसर से जूझ रहे हैं। ईडी ने पिछले साल सितंबर में नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था। उन पर 538.62 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। यह रकम केनरा बैंक ने जेट एयरवेज को लोन के रूप में दी थी। उनकी पत्नी अनीता गोयल को नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए स्पेशल कोर्ट ने उसी दिन उन्हें जमानत दे दी थी।

अनीता गोयल जेट एयरवेज के ऑपरेशंस के साथ जुड़ी हुई थीं और कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट थीं। साल 2015 में वह एयरलाइन की नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया लेकिन वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनी रहीं। नरेश गोयल को बांबे हाई कोर्ट ने छह मई को दो महीने के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी थी। फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था लेकिन उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करने की अनुमति दे दी थी। बाद में उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कभी देश की सबसे बेस्ट एयरलाइन माने जाने वाली जेट एयरवेज की उड़ानें 17 अप्रैल 2019 से बंद है।

अर्श से फर्श पर : नरेश गोयल ने साल 1991 में एयर टैक्सी के रूप में जेट एयरवेज की शुरुआत की। एक साल में ही उन्होंने चार विमानों का बेड़ा तैयार कर लिया और जेट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान शुरू हो गई। साल 2007 में एयर सहारा को टेकओवर करने के बाद 2010 तक जेट एयरवेज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। लेकिन जल्दी ही कंपनी की मुसीबतें बढ़ने लगीं। मार्च 2019 में उन्हें अपने पद से हटना पड़ा और उसी साल जेट एयरवेज का संचालन भी बंद हो गया।

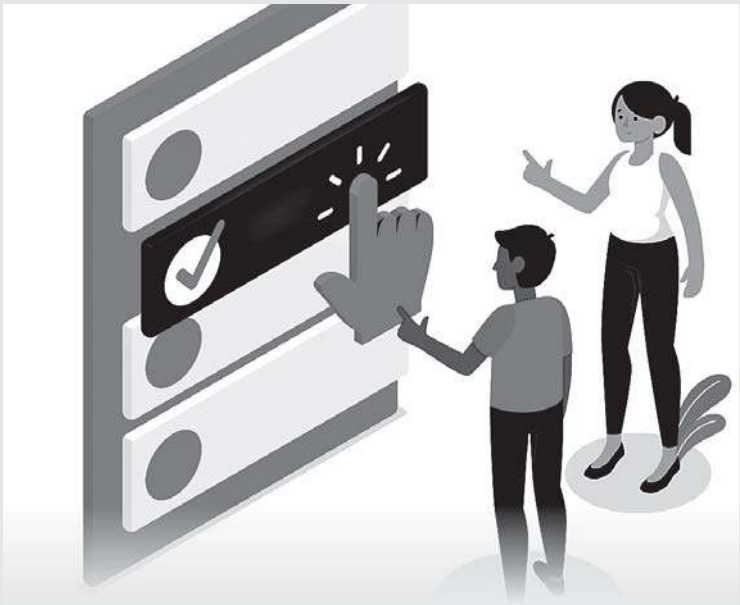

एग्जिट पोल का सबसे भरोसेमंद चेहरा जिसने अपने सभी एग्जिट और ओपिनियन पोल नतीजों में इसे साबित भी किया है

एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ताः '2019 की तुलना में 2024 में वोटिंग पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है'

प्रदीप गुप्ता ने यह भी कहा है कि इसकी बहुत कम संभावना है कि चुनाव बीच में ही बदल जायेगा. उन्होंने कहा, द्विध्रुवीय मुकाबले में 30-40% मतदाता कमोबेश एकजुट या स्थिर होते हैं।

एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने पिछले दिनों कहा कि उन्हें 2019 की तुलना में मौजूदा लोकसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस समय देश में बड़े बदलाव के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, तो गुप्ता ने कहा "हां, मैं तो यही कह रहा हूं।" हालाँकि, उन्होंने कहा कि इसका संख्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 303 और एनडीए ने 353 सीटें जीती थीं.

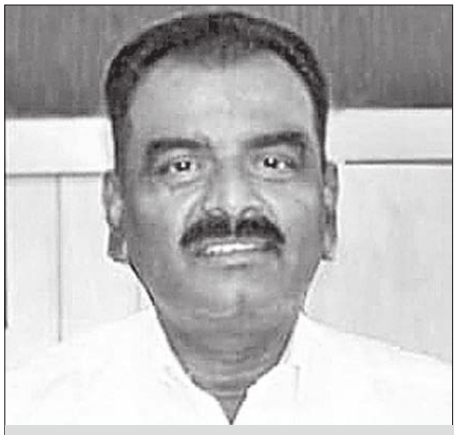

निलेन्दु सिंह ने सीसीएल के सीएमडी का लिया पदभार

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) से चयनोपरांत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड के आदेशों के आलोक में श्री निलेन्दु कुमार सिंह ने 30 मई को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया ।

इस कार्यभार से पूर्व, श्री सिंह ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक तकनीकी (परियोजना एवं योजना) पद पर कार्यरत थे। श्री सिंह ने वर्ष 1989 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से खनन इंजीनियरिंग (बी.टेक) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1994 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।

अपने शिक्षण के उपरांत वर्ष 1989 में कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से अपने करियर की शुरुआत की । श्री सिंह ने 2011 तक सीसीएल में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इस दौरान वे पिपरवार, अशोका, उरीमारी और कल्याणी इत्यादि परियोजनाओं में खान प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद, जनवरी, 2012 में उनकी पदस्थापना एसईसीएल में हुई । जहां उन्होंने गेवरा में खान प्रबंधक; दीपका और छाल परियोजना में उप क्षेत्र प्रबंधक (एजेंट) और एसईसीएल के दीपका क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र और रायगढ़ क्षेत्र में महाप्रबंधक के रूप में अपना योगदान दिया ।

श्री सिंह के पास मेगा ओपन कास्ट खदानों में काम करने, एफएमसी परियोजनाओं के संचालन , साइडिंग शुरू करने, नई खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उच्चतम क्षमता वाले एचईएमएम के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। श्री निलेन्दु कुमार सिंह ने खनन तकनीकों में अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1997 में ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा किया है। उन्हें खेल और पेंटिंग में गहरी रुचि है। उन्होंने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर पर वॉलीबॉल का प्रतिनिधित्व किया है। कोयला उद्योग में तीन दशकों से अधिक के विशाल अनुभव के धनी, श्री सिंह विभिन्न नई खनन पद्धतियों की शुरुआत करने में और कंपनी के कामकाज में सुधार लाने में अपना अहम योगदान दिया है। इसके साथ-साथ विभिन्न श्रमसंगठनों व कंपनी के हितधारकों को साथ लेकर कार्य करने का उन्हें कोयला उद्योग में विविध और दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त है ।

कोयला उद्योग में श्री सिंह के तीन दशकों से अधिक के अनुभव से टीम सीसीएल को लाभ मिलेगा।

एसईसीएल ने सरकारी खजाने में दिया रिकार्ड 17,474 करोड़ रु का योगदान

कोल इंडिया (सीआईएल) की दूसरी बड़ी अनुषांगिक कंपनी एसईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सरकारी खजाने में रिकॉर्ड 17,474 करोड़ का योगदान दिया है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष 2022- 2023 के मुकाबले 3,024 करोड़ अधिक है। एसईसीएल ने केन्द्र सरकार के खजाने में 10,000 करोड़ से अधिक जमा किए गए हैं, जिसमें 7600 करोड़ से अधिक का जीएसटी भुगतान शामिल है।

इसी तरह विभिन्न करों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 5,883 करोड़ एवं मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 1,472 करोड़ का भुगतान किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023- 2024 में आयकर भुगतान लगभग दोगुना किया गया है।

यहां बताना होगा कि वित्तीय वर्ष 2023- 2024 एसईसीएल के लिए ऐतिहासिक नतीजे वाला रहा है। कम्पनी ने 187 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया

जो कि स्थापना से किसी भी एक वर्ष का सर्वाधिक उत्पादन है। एसईसीएल ने वार्षिक आधार पर लगातार दूसरे वर्ष 20 मिलियन टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की। 180.5 मिलियन टन कोयला उपभोक्ताओं को प्रेषित किया जिसमें सर्वाधिक 147.8 मिलियन टन कोयला देश के विद्युत संयंत्रों को भेजा गया, यह किसी एक वर्ष में कम्पनी द्वारा पावर सेक्टर को दिया गया सर्वाधिक डिस्पैच है। ओव्हर बर्डन रिमूवल (ओबीआर) में कम्पनी ने ऐतिहासिक परिणाम दिए व 22 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 323.2 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबीआर निष्कासित किया।

सीईआरसी प्रतिनिधिमंडल ने पकरी बरवाडीह माइंस का दौरा किया

केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण (सीईआरसी) के अध्यक्ष, श्री जिष्णु बरुआ, आईएएस (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में एक सीईआरसी प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों कोयला खनन मुख्यालय/एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल), रांची का दौरा किया।

श्री शिवम श्रीवास्तव, निदेशक (ईंधन), एनटीपीसी और अध्यक्ष (एनएमएल) ने प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और श्री जयशंकर श्रीनिवासन, निदेशक (वित्त), एनटीपीसी की गरिमामय उपस्थिति में सीईआरसी प्रतिनिधिमंडल को खनन में आने वाले संचालन और चुनौतियों से अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल की रांची यात्रा के दौरान, टीम ने एनटीपीसी कोयला खनन क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एनटीपीसी और कोयला खनन कार्यों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ बातचीत की।

सीईआरसी प्रतिनिधिमंडल ने एनटीपीसी की फ्लैगशिप परियोजना, हजारीबाग में पकरी बरवाडीह माइंस का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने खनन कार्यों का अध्ययन करने के लिए एनटीपीसी कोयला खदानों का दौरा किया। इस दौरे में पकरी बरवाडीह खान का ऑपरेशन और ओवरबर्डन (ओबी) क्षेत्र का दौरा किया । इस अवसर पर, प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने महिला डंप चालक से बातचीत की और उन्हें अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया । सीईआरसी टीम ने एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल) के बैनर तले हाल के दिनों में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और शानदार प्रदर्शन हासिल करने के लिए एनटीपीसी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।प्रतिनिधिमंडल दल में श्री अरुण गोयल, सदस्य (वित्त), श्री प्रवास कुमार सिंह, सदस्य (कानून), श्री हरप्रीत सिंह प्रूथी, सचिव, श्री राजीव पुष्करणा, प्रमुख, वित्त प्रभाग, डॉ. एस के चटर्जी प्रमुख, नियामक मामले शामिल थे।.

श्री अनिमेष जैन, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (कोयला खनन) और सीईओ (एनएमएल), फैज़ तैयब, परियोजना प्रमुख, पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना, श्री रजनीश रस्तोगी, सीजीएम (एचआर), कॉर्पोरेट वाणिज्यिक टीम के सदस्यों के साथ विभिन्न विभागों के प्रमुख दौरे के दौरान मौजूद थे ।

अदाणी फाउंडेशन द्वारा राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था

अदाणी पावर लिमिटेड हमेशा अपने लोकहित के कार्यों के माध्यम से समुदाय कल्याण और सतत विकास की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता रहा है। इसी क्रम में अदाणी फाउंडेशन द्वारा मोतिया स्थित पावर प्लांट से लेकर गोड्डा शहर के लगभग सभी भीड़-भाड़ वाली तेरह जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। दरअसल चिलचिलाती धूप, उमस व लू के चलते राहगीरों व बाजार आने वाले लोगों को पीने के पानी के लिए दिक्कत उठानी पड़ रही थी। अब प्याऊ की व्यवस्था हो जाने से इस मार्ग पर आने-जाने वाले राहगीरों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे इस चिलचिलाती गर्मी में राहगीरों को प्यास बुझाने में मदद मिल रही है। इन प्याऊ के स्थानों का चयन राहगीरों को अधिकतम लाभ हेतु तथा उनकी सहज पहुँच योग्य बनाने के लिए किया गया है। यह तेरह स्थान- अदाणी पावर प्लांट गेट के समीप, आईटीआई मोड़, रेलवे स्टेशन मोड़, करगिल चौक पर कचहरी गेट के सामने, बस स्टैंड के सामने, मिशन चौक के निकट, मेला मैदान के निकट सब्जी मंडी के सामने, रौतारा चौक, गंगटा काली मंदिर चौक, कदवा टोला, शिवपुर रत्नेश्वर धाम मंदिर के निकट, गोड्डा सदर अस्पताल के निकट, हटिया चौक हनुमान मंदिर के निकट हैं, जहां आने- जाने वाले राहगीर रुक कर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अदाणी फाउंडेशन की ओर से ही सुबह शाम घड़ों में पानी भरने के लिए कर्मचारी की ड्यूटी भी लगा दी गई है। अदाणी की इस पहल की चारों ओर सराहना हो रही है।

मिश्र धातु निगम अतिरिक्त महाप्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार

सीबीआई ने गत दिनों मिश्र धातु निगम (मिधानी) के अतिरिक्त महाप्रबंधक टी. जानकी राव को कीट नियंत्रण कार्य के भुगतान के लिए एक ठेकेदार से उसके मासिक बिल को आगे बढ़ाने के लिए 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सीबीआई 4 अप्रैल को प्रिसिजन फ्यूमिगेशन सर्विसेज, मेहदीपट्टनम के प्रबंध निदेशक एन. श्रीनिवास रेड्डी की शिकायत पर कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने एक माइक्रो एसडी कार्ड जमा किया था जिसमें अधिकारी के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। सीबीआई ने कहा कि राव ने एक कर्मचारी ए नारायण के माध्यम से शिकायतकर्ता से 2 मार्च और 3 मार्च 2024 को 30,000 रुपये लिए थे और एक और रिश्वत की मांग की थी।

एनटीपीसी मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा

एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय/एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, रांची ,स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने के लिए 16 मई से 31 मई, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा-2024 मना रहा है। यह स्वच्छता पखवाड़े में स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय समुदाय को शामिल किया जायेगा। स्वच्छता पखवाड़ा के शुभारंभ के साथ, स्वच्छता शपथ को मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री रजनीश रस्तोगी ने विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में दिलाई। शपथ में स्वच्छता को बढ़ावा देने और देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता मिशन में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वेच्छा से एक वर्ष में 100 घंटे का समय और सप्ताह में कम से कम 2 घंटे समर्पित करने पर जोर दिया गया। बाद में कर्मचारियों और सहयोगियों ने "मैं स्वच्छता राजदूत हूं " थीम के साथ सेल्फी जोन में भाग लिया, स्वच्छ भारत अभियान की पहल को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को दोहराया।

स्वच्छता पखवाड़ा उत्सव के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, स्कूली बच्चों के लिए विषयगत पेंटिंग प्रतियोगिता, कचरे प्रबंधन पर कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

एसईसीएल मुख्यालय में खनिक दिवस

सीएमडी ने कंपनी के नाम, नमक एवं निशान के प्रति समर्पित रहने किया आह्वान

एसईसीएल (एसईसीएल) वसंत विहार स्थित रविन्द्र भवन के टैगोर हाल में खनिक दिवस का आयोजन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डा. प्रेम सागर मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

निदेशक (वित्त) जी. श्रीनिवासन , निदेशक तकनीकी (संचालन) एस.एन. कापरी, मुख्य सतर्कता अधिकारीजयंत कुमार खमारी, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) एन. फ्रेंकलिन जयकुमार, निदेशक (कार्मिक) बिरंची दास, पूर्व निदेशक तकनीकी एन.के. सिंह, सी.एल. श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक (कार्मिक) के.के. श्रीवास्तव, एसईसीएल संचालन समिति के हरिद्वार सिंह (एटक), बीएम मनोहर (सीटू), एके पाण्डेय (सीएमओएआई) के विशिष्ट आतिथ्य, एसईसीएल सुरक्षा समिति के आनंद मिश्रा (एचएमएस), बी. धर्माराव (एटक), संजय सिंह (बीएमएस), कमलेश शर्मा (एसईकेएमसी), इन्द्रदेव चैहान (सीटू), जीएम प्रसाद (सीएमओएआई), सिस्टा अध्यक्ष एआर सिदार, सिस्टा महासचिव आर.पी. खाण्डे, कौंसिल अध्यक्ष ओपी नवरंग, कौंसिल महासचिव ए विश्वास, अध्यक्ष ओबीसी एसोसिएशन अनिरूद्ध कुमार चन्द्रा, श्रद्धा महिला मण्डल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा उपाध्यक्षागण राजी श्रीनिवासन, संगीता कापरी, सुजाता खमारी, श्रीमती अनीता फ्रेंकलिन समारोह में उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया गया उपरांत खनिक प्रतिमा पर माल्यार्पण मुख्य अतिथि एवं समस्त अतिथियों द्वारा किया गया उपरांत मुख्य अतिथि तथा मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप-प्रज्जवलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। कोल इण्डिया कारपोरेट गीत बजाया गया एवं शहीद श्रमवीरों के सम्मान में समस्त उपस्थितों द्वारा दो मिनट का मौन रखा गया। संकल्प का पठन सीएमडी डा. प्रेम सागर मिश्रा द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन महाप्रबंधक (विक्रय/विपणन) सीबी सिंह ने प्रस्तुत किया ।

मुख्य अतिथि डा. प्रेम सागर मिश्रा ने सभी उपस्थितों को खनिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को हमारी कंपनी एसईसीएल के नाम, नमक और निशान के प्रति सदैव समर्पित रहते हुए इसकी उन्नति के लिए लिए अनवरत श्रम करते रहना है। उन्होने कहा कि एसईसीएल की सफलता किसी एक व्यक्ति या एक दिन की मेहनत का फल नहीं है बल्कि यह हमारे श्रमवीरों के कई वर्षों के अनुभव, परिश्रम एवं समर्पण का प्रतिफल है।

विशिष्ट अतिथि निदेशक निदेशक (वित्त) जी. श्रीनिवासन , निदेशक तकनीकी (संचालन) एस.एन. कापरी, मुख्य सतर्कता अधिकारी जयंत कुमार खमारी, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना), एन. फ्रेंकलिन जयकुमार, निदेशक (कार्मिक), बिरंची दास, ने अपने उद्बोधन में कहा कि सीएमडी डॉ प्रेम सागर मिश्रा कि आगुवाई में पिछले दो वर्षों में कंपनी एतेहासिक उत्पादन के साथ साथ सभी पैरामीटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होने कहा कि आज का यह शुभ दिन श्रमिकों के सेवाओं के सम्मान का दिन है। निःसंदेह कोयला खान का श्रमिक दिन-रात मेहनत करके राष्ट्र की ऊर्जा शक्ति बढ़ाने एवं राष्ट्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। उन्होंने अपने सम्बोधन में अपने कर्मियों के लिए किए गए कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अंत में उन्होंने अपने प्रेरणास्पद शब्दों से उत्कृष्ठता पुरस्कार पाने वाले समस्त कर्मियों को बधाई दिया।

स अवसर एसईसीएल परिवार द्वारा सीएमडी डॉ प्रेम सागर मिश्रा को खनन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान एवं उपलब्धियों के लिए सर्वोत्कृष्ट खनिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया।

श्रमवीर पुरस्कृत हुएः ओव्हरआल परफारमेंन्स अण्डरग्राउण्ड माईन्स ग्रुप-ए- प्रथम-विजय वेस्ट यूजी, द्वितीय-खैरहा यूजी, तृतीय-रानीअटारी यूजी रहा। ग्रुप-बी-प्रथम-पाण्डवपारा यूजी, द्वितीय-झीरिया यूजी, तृतीय-शिवानी यूजी रहा। ग्रुप-सी में प्रथम-राजेन्द्रा यूजी, द्वितीय-नौरोजाबाद वेस्ट यूजी, तृतीय-बलरामपुर यूजी रहा।

ओव्हरआल परफारमेन्स ओपनकास्ट माईन-ग्रुप-ए-प्रथम-बरौद ओसी, द्वितीय-छाल ओसी, तृतीय-दीपका ओसी रहा। ग्रुप बी-प्रथम-जामपाली ओसी, द्वितीय-अमलाई ओसी, तृतीय-बिजारी ओसी रहा। ग्रुप सी-प्रथम-अमगांव ओसी, द्वितीय-राजनगर ओसी, तृतीय-रामपुर बटुरा ओसी रहा।

ओव्हरआल परफारमेन्स एरिया वाईस-ग्रुप-ए-प्रथम-रायगढ़ एरिया, द्वितीय-गेवरा एरिया, तृतीय-कुसमुण्डा एरिया रहा। ग्रुप-बी-प्रथम-सोहागपुर एरिया, द्वितीय-हसदेव एरिया, तृतीय-भटगांव एरिया रहा। ग्रुप-सी-प्रथम-बिश्रामपुर एरिया, द्वितीय-जोहिला एरिया, तृतीय-बैकुण्ठपुर एरिया रहा।

बेस्ट एसडीएल आपरेटर-प्रथम-शनीराम नौरोजाबाद वेस्ट जोहिला, द्वितीय-प्रदुमन कुमार भटगांव यूजी

भटगांव, तृतीय-महेश कुमार कटकोना बैकुण्ठपुर रहे। बेस्ट एलएचडी आपरेटर-प्रथम-बलजीत शिवानी यूजी भटगांव, द्वितीय-हेतराम बगदेवा यूजी कोरबा, तृतीय-स्वामीदीन राजेन्द्रा यूजी सोहागपुर रहे। बेस्ट ड्रिलर-प्रथम-शिवशंकर दामिनी यूजी सोहागपुर, द्वितीय-दिचंद बगदेवा यूजी कोरबा, तृतीय-भैया लाल पाली यूजी जोहिला रहे। बेस्ट यूडीएम ऑपरेटर-प्रथम-कौशल प्रसाद झिलमिली यूजी बैकुण्ठपुर, द्वितीय-कुलदीप बलरामपुर यूजी बिश्रामपुर, तृतीय-शमशेर सिंह राजनगर आरओ यूजी हसदेव रहे। बेस्ट अण्डरग्राऊंड वर्कर-प्रथम-रामलाल पटेल राजनगर आरओ यूजी हसदेव, द्वितीय-भगवानदीन जमुना 9/10 यूजी जमुना कोतमा, तृतीय-जगबन्धु बेहरा विजय वेस्ट यूजी चिरमिरी रहे।

बेस्ट शावेल आपरेटर-प्रथम-मुन्ना राम साहू गेवरा ओसी गेवरा, द्वितीय-जसबीर सिंह दीपका ओसी दीपका, तृतीय-संजीत दत्ता चिरमिरी ओसी चिरमिरी रहे। बेस्ट डम्पर आपरेटर-प्रथम-सुनील यादव दीपका ओसी दीपका, द्वितीय-एस. दयाल बीपी गेवरा ओसी गेवरा, तृतीय-हेमंत तिवारी अमलाई ओसी सोहागपुर रहे। बेस्ट ड्रगलाईन आपरेटर-प्रथम-रामलाल पटेल चिरमिरी ओसी चिरमिरी रहे। बेस्ट ड्रिल आपरेटर-प्रथम-माखनलाल कुसमुण्डा ओसी कुसमुण्डा, द्वितीय-छोटे आमाडांड ओसी जमुना कोतमा, तृतीय-आरएस त्रिपाठी अमलाई ओसी सोहागपुर रहे। बेस्ट डोजर आपरेटर-प्रथम-मुख्तार हुसैन अमगांव ओसी बिश्रामपुर, द्वितीय-सोहिल खान कुसमुण्डा ओसी कुसमुण्डा, तृतीय-देवेन्द्र कुमार जामपाली ओसी रायगढ़ रहे।

सीएसआर अवार्ड-प्रथम-गेवरा क्षेत्र, द्वितीय-बैकुण्ठपुर क्षेत्र, तृतीय-रायगढ़ क्षेत्र रहा। इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स अवार्ड-प्रथम-औद्योगिक संबंध विभाग मुख्यालय बिलासपुर, द्वितीय-कुसमुण्डा क्षेत्र, तृतीय-गेवरा क्षेत्र रहा। क्वालिटी आफ लाईफ अवार्ड-प्रथम बैकुण्ठपुर क्षेत्र, द्वितीय-गेवरा क्षेत्र, तृतीय-चिरमिरी क्षेत्र रहा। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड-प्रथम-गेवरा क्षेत्र, द्वितीय-बिश्रामपुर क्षेत्र, तृतीय-जोहिला क्षेत्र रहा। प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट माईलस्टोन एचीवमेन्ट अवार्ड-प्रथम-गेवरा क्षेत्र, द्वितीय-कुसमुण्डा, तृतीय-सोहागपुर क्षेत्र, चतुर्थ-रायगढ़ क्षेत्र, पंचम-बिश्रामपुर एवं दीपका क्षेत्र रहा। सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड-प्रथम-सोहागपुर क्षेत्र, द्वितीय-जोहिला क्षेत्र, तृतीय-रायगढ़ क्षेत्र रहा। एचआरडी अवार्ड-प्रथम-हसदेव क्षेत्र, द्वितीय-कुसमुण्डा क्षेत्र, तृतीय-बैकुण्ठपुर क्षेत्र रहा। पब्लिक रिलेशन्स अवार्ड-प्रथम-रायगढ़ क्षेत्र, द्वितीय-दीपका क्षेत्र, तृतीय-कुसमुण्डा क्षेत्र रहा। राजभाषा अवार्ड-प्रथम-कोरबा क्षेत्र, द्वितीय-जोहिला क्षेत्र, तृतीय-रायगढ़ क्षेत्र रहा।

समन्वय पुरस्कार-श्रद्धा महिला मण्डल बिलासपुर, महिला मंडल में प्रथम-सुहानी महिला समिति भटगांव, द्वितीय-अलंकृता महिला समिति जमुना कोतमा, तृतीय-सुरभि महिला समिति सोहागपुर रहा। इसके साथ ही तकनीकी/गैर-तकनीकी नवाचार के लिए भी 5 पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर निदेशक मण्डल द्वारा सर्वोत्कृष्ठ खनिक सम्मान से एसईसीएल के प्रथम पुरूष डा. प्रेम सागर मिश्रा को शाल, श्रीफल, पुष्प प्रदान कर सम्मानित किया गया।

हम सभी को हमारी कंपनी एसईसीएल के नाम, नमक और निशान के प्रति सदैव समर्पित रहते हुए इसकी उन्नति के लिए लिए अनवरत श्रम करते रहना है।

विशिष्ट अतिथि पूर्व निदेशक तकनीकी श्री एन.के. सिंह, सी.एल. श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक (कार्मिक) के.के. श्रीवास्तव ने कहा कि अपने स्थापना काल से ही कीर्तिमानों के शिखर पर विराजमान एसईसीएल जैसे प्रतिष्ठापूर्ण संगठन से जुड़ना अपने आप में एक सम्मान व अभिमान का विषय है। उन्होंने एसईसीएल एवं इसमें कार्यरत कर्मियों को सपरिवार उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की।

एसईसीएल संचालन समिति के हरिद्वार सिंह (एटक), बीएम मनोहर (सीटू), एके पाण्डेय (सीएमओएआई) एवं सुरक्षा समिति के आनंद मिश्रा (एचएमएस), संजय सिंह (बीएमएस), कमलेश शर्मा (एसईकेएमसी) ने अपने उद्बोधन में श्रमिक दिवस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए एसईसीएल प्रबंधन द्वारा श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

रवीन्द्र भवन के कार्यक्रम से पूर्व एसईसीएल मुख्यालय प्रांगण में आयोजित समारोह में निदेशक (कार्मिक) श्री बिरंची दास ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए उपरांत अंबेडकर प्रतिमा व खनिक प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं श्रमसंघ प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में उद्घोषणा का दायित्व वरुण शर्मा, प्रबन्धक (कार्मिक) एवं सी. अनुराधा उप-प्रबन्धक (ईएंडएम) ने निभाया। कार्यक्रम के अंत में मंचस्थ अतिथियों के करकमलों से विभिन्न केटेगरी के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। अंत में उपस्थितों को धन्यवाद ज्ञापन उप महाप्रबंधक (कार्मिक/अधिकारी स्थापना) श्रीमती सुजाता रानी द्वारा दिया गया।

सीवीओ ने नीलजई ओपन कास्ट खदान का निरीक्षण किया

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के अनुपालन में, कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रिवेंटिव सतर्कता और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में कोल इंडिया के सीवीओ ब्रजेश कुमार त्रिपाठी तथा डबल्यूसीएल के सीवीओ अजय मधुकर म्हेत्रे ने बहु-विषयक अधिकारियों की टीम के साथ डबल्यूसीएल वाणी क्षेत्र की नीलजई ओपन कास्ट खदान तथा घुगस रेलवे साइडिंग का औचक निरीक्षण किया।

यह निरीक्षण खदानों में वास्तविक रूप से उपलब्ध कोल स्टॉक के साथ बुक स्टॉक की सटीकता की जांच करने के लिए किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान वेटब्रिज (दोनों छोर पर वजन), बूम-बैरियर और क्रशर, RFID स्कैनर की कार्यप्रणाली जैसी आईटी पहलों की प्रभावकारिता की भी जांच की गई। इसके उपरांत क्षेत्रों में अधिकारियों के बीच प्रिवेंटिव सतर्कता और सुशासन पर जागरूकता लाने हेतु कोल इंडिया के सीवीओ ब्रजेश कुमार त्रिपाठी तथा डबल्यूसीएल के सीवीओ अजय मधुकर म्हेत्रे ने चंद्रपुर क्षेत्र में आयोजित एक कार्यशाला को सम्बोधित किया, जिसमें उस इलाक़े के डबल्यूसीएल के पांचो एरिया के लगभग 170 अधिकारयों ने भाग लिया । सीवीओ सीआईएल श्री त्रिपाठी ने बताया कि कोल इंडिया कम्पनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है तथा इसे मूल्यवान कम्पनी से मूल्यों की कम्पनी बनाना है।

केन्द्रीय खनिज सचिव का खनन व खनिज उद्योगों में ग्रीन एनर्जी के उपयोग पर जोर

केंद्रीय खनिज सचिव व्ही.एल. कान्ता राव की अध्यक्षता में पिछले दिनों नवा रायपुर अटल नगर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, पर्यावरण तथा खनिज विभाग के सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर प्रदेश में खनन गतिविधियों की समीक्षा की गई।

बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी.दयानंद ने प्रदेश में खनिज साधन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यों के बारे में बिन्दुवार जानकारी दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव अविनाश चंपावत, पर्यावरण विभाग की सचिव आर. संगीता, खनिज विभाग के संचालक सुनील जैन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

केन्द्रीय सचिव श्री राव ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश में खनन तथा खनिज उद्योगों की गतिविधियों और कार्यों की जानकारी ली और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से उत्खनन कार्य को अधिक बेहतर बनाने और माइनिंग गतिविधियों के सुगम संचालन के संबंध में उनके सुझाव लिये। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि उत्खनन क्षेत्र में ग्रीन माईनिंग की नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि खनन और खनिज उद्योगों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने खनिज संसाधनों का जीडीपी में वर्तमान में दो प्रतिशत की भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया। केन्द्रीय खनिज सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की उपलब्धता और खनन गतिविधियों में देश का अग्रणी राज्य है। खनन गतिविधियों में प्रदेश को और आगे लेकर जाना है, जो आर्थिक दृष्टि से भी देश और प्रदेश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुझाव दिया।

बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भूमि संबंधी, खनिज लौह अयस्क की कमी, वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की जरूरत बताई। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि स्वीकृत खदानों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाने के लिए बिडर्स और संबंधित विभागों के बीच अधिक समन्वय से काम किया जाना चाहिए। इसके

> केन्द्रीय सचिव श्री राव ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश में खनन तथा खनिज उद्योगों की गतिविधियों और कार्यों की जानकारी ली और उनकी समस्याएं भी सुनी।

लिए उन्होंने खनिज साधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में ऐसे समस्त विभागों के सचिवों, जिनसे स्टेकहोल्डर्स को सहमतियां लेनी होती है, की माईनिंग रिव्यू कमिटी गठित की जाए। साथ ही समय-समय पर बैठक आयोजित कर स्वीकृत ब्लाकों में खनन संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा।

केन्द्रीय सचिव ने खनिज साधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसी खदाने जो बंद हो चुकी हैं उनमें अवैध उत्खनन न हो, बंद खदानों में यदि खनिज है तो उनमें खनन के लिए जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां डीएमएफ का ऑनलाईन पोर्टल संचालित है। केन्द्रीय सचिव ने डीएमएफ से हितग्राहीमूलक नवीन गतिविधियों को बढ़ाने, खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मांग पर अधोसंरचना विकास के काम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि माईनिंग क्लोजर और बंद खदानों को हैण्ड ओवर करने की समीक्षा राज्य स्तर पर नियमित रूप से की जाए।

उन्होंने खनिज ब्लाक्स के ऑपरेशनल स्टेटस की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने जानकारी देते हुए बताया कि खनन के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य गंभीरता के साथ किया जा रहा है। इसके लिए संस्थाओं को आवश्यक आर्थिक सहयोग भी मुहैया कराया जाता है। उन्होंने खनन क्षेत्र की नीलामी के बाद ऑपरेशनल बनाने के लिए आगे की कार्रवाई की सुगमता और मॉनिटरिंग के लिए सेल गठन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपॉजिटरी के संचालन और उसके उपयोगिता की जानकारी भी साझा की।

खनिज साधन विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने कहा कि खनन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स ने आज महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने केन्द्रीय सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की बात दोहराई। बैठक में खनिज विभाग के संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान ने प्रदेश में खनन गतिविधियों और उनके महत्व पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

एस सुरेश कुमार को मेंबर टेक्निकल का अतिरिक्त प्रभार

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं डीवीसी के अध्यक्ष एस सुरेश कुमार को 1 जून से 3 माह के लिए डीवीसी के मेंबर टेक्निकल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. मिनिस्ट्री आफ पावर के अंडर सेक्रेटरी जे मिश्रा का इस आशय का हस्ताक्षर युक्त आदेश 9 में को जारी किया गया है. डीवीसी अध्यक्ष को उक्त प्रभार 31 अगस्त तक के लिए या स्थायी रूप से मेंबर टेक्निकल की नियुक्ति तक के लिए दिया गया है. विदित हो कि डीवीसी के मेंबर टेक्निकल एम रघुराम 31मई को अवकाश प्राप्त कर रहे हैं.

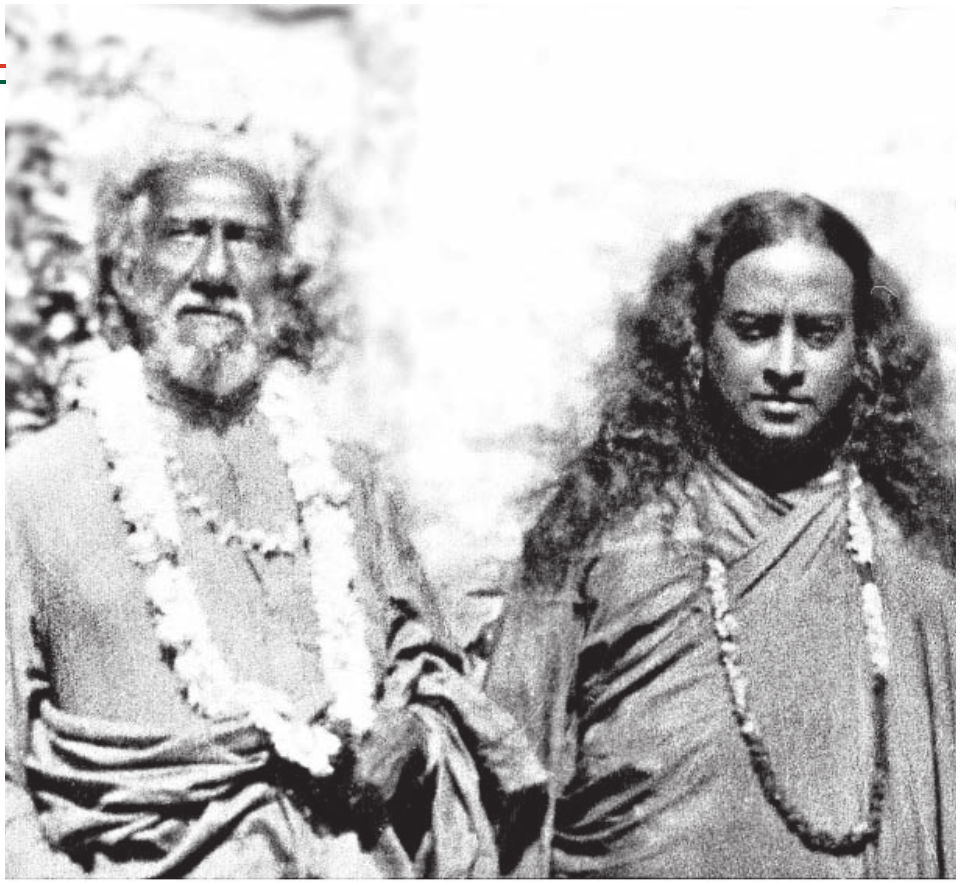

एक ज्ञानावतार का हृदय

श्री श्री स्वामी श्रीयुक्तेश्वर गिरि जी का 169वां आविर्भाव दिवस

▪ संध्या एस. नायर

"मैं तुम्हें अपना अशर्त प्रेम प्रदान करता हूँ," अपने निर्मल प्रेम के इस शाश्वत वचन के साथ, "ज्ञान के अवतार" अर्थात् ज्ञानावतार स्वामी श्रीयुक्तेश्वर गिरि ने अपने आश्रम में युवा मुकुन्द का स्वागत किया। यही मुकुन्द कालान्तर में परमहंस योगानन्द के नाम से, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया के संस्थापक, पश्चिम में योग के जनक, तथा अत्यन्त लोकप्रिय आध्यात्मिक गौरव ग्रन्थ "योगी कथामृत" के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यद्यपि घटनाओं के दैवीय नाटक से ऐसा प्रतीत नहीं होता था, परन्तु समबुद्धि गुरुदेव को उनकी इस यात्रा का पहले से ही ज्ञान था और वे अनेक वर्षों से उत्सुकतापूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

जनवरी 1894 में प्रयागराज के पवित्र कुम्भ मेले में श्रीयुक्तेश्वरजी की भेंट हिमालय के अमर गुरु महावतार बाबाजी से हुई थी। यह जानते हुए कि योगानन्दजी पुनः अवतरित हो चुके हैं (मुकुन्द का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था), बाबाजी ने "पश्चिम में योग के प्रसार" के लिए प्रशिक्षण हेतु श्रीयुक्तेश्वरजी के पास एक युवा शिष्य भेजने का वचन दिया था। बाबाजी ने उनसे सनातन धर्म और ईसाई धर्म के धर्मग्रन्थों में निहित एकता पर एक संक्षिप्त पुस्तक लिखने के लिए भी कहा था। उन्होंने इन शब्दों के साथ उनकी सराहना की, "मैंने जान लिया था तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रूचि है। समस्त मानवजाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अन्तःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया था।" उनसे समानार्थी उद्धरणों द्वारा यह दिखाने के लिए कहा गया था कि "ईश्वर के सभी प्रेरित, ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया है।"

श्रीयुक्तेश्वरजी ने अपनी स्वभावगत विनम्रता के साथ इस दैवी आदेश को स्वीकार किया, और अन्तर्ज्ञानात्मक बोध एवं गहन अध्ययन के साथ उन्होंने अल्पसमय में ही "कैवल्य दर्शनम् " पुस्तक की रचना पूर्ण कर ली। महान् प्रभु यीशु के शब्दों को उद्धृत करते हुए, "उन्होंने दिखाया कि उनके उपदेशों में और वेदवाक्यों में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं था।" इसके अतिरिक्त, पुस्तक के विभिन्न सूत्रों में श्रीयुक्तेश्वरजी मनुष्य के चित्त की पाँच अवस्थाओं की व्याख्या करते हैं, अर्थात् अन्धकारयुक्त (मूढ़), गतियुक्त (विक्षिप्त), स्थिर (क्षिप्त), भक्तियुक्त (एकाग्र) तथा शुद्ध (निरुद्ध)। वे स्पष्ट करते हैं कि, "चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर मनुष्य का वर्गीकरण किया जाता है, तथा उसकी उन्नति की अवस्था निर्धारित की जाती है।" उनका जन्म 10 मई, 1855 को बंगाल के श्रीरामपुर में हुआ था और उनका पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था। वे महान् योगी श्री लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। आगे चलकर वे स्वामी सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गए और उन्हें स्वामी श्रीयुक्तेश्वर गिरि का नया नाम मिला।

बाबाजी को दिया हुआ अपना वचन निभाते हुए श्रीयुक्तेश्वरजी ने युवा योगानन्दजी को अपने आश्रम में एक दशक तक प्रशिक्षण प्रदान किया। योगानन्दजी ने अपनी पुस्तक "योगी कथामृत" के एक प्रकरण, "अपने गुरु के आश्रम की कालावधि" में श्रीयुक्तेश्वरजी—बंगाल के सिंह—के साथ व्यतीत किये अपने जीवन का एक भावपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं कि उन्होंने अपने गुरुदेव को कभी भी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त, या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। उनकी आभा "सुखद शान्ति" की थी। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में अनेक शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों के साथ क्रियायोग (ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान की प्राचीन वैज्ञानिक प्रविधि) के अभ्यास की आवश्यकता का स्मरण कराया, "माया का अन्धकार धीरे-धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ, अपने अन्तर् में अपने घर की ओर भाग चलें।"

जो शिष्य उनका परामर्श चाहते थे, श्रीयुक्तेश्वरजी उनके प्रति एक गंभीर उत्तरदायित्व का अनुभव करते थे। वे उन्हें अपने प्रशिक्षण में कठोरता की अग्नि में तपाकर शुद्ध करने का प्रयास करते थे; इस अग्नि की तप्तता साधारण सहनशक्ति से परे होती थी। जब योगानन्दजी ने अपने गुरु के कार्य की अवैयक्तिक प्रकृति को समझा, तो उन्होंने उनकी विश्वसनीयता, विचारशीलता और मौन प्रेम का अनुभव किया।

योगानन्दजी अपने प्रिय गुरुदेव के बारे में लिखते हैं, "उनके विलक्षण स्वभाव को पूरी तरह पहचानना कठिन था। उनका स्वभाव गम्भीर, स्थिर और बाह्य जगत् के लिए दुर्बोध्य था, जिसके सारे मूल्यों को कब के पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ गए थे।" अधिक जानकारी : yssofindia.org.

महिला युवा खिलाड़ियों को निखारने व हॉकी को शीर्ष पर ले जाने वाला कदम

अपेक्षा से अधिक उपलब्धियों से भरा रहा रांची में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग

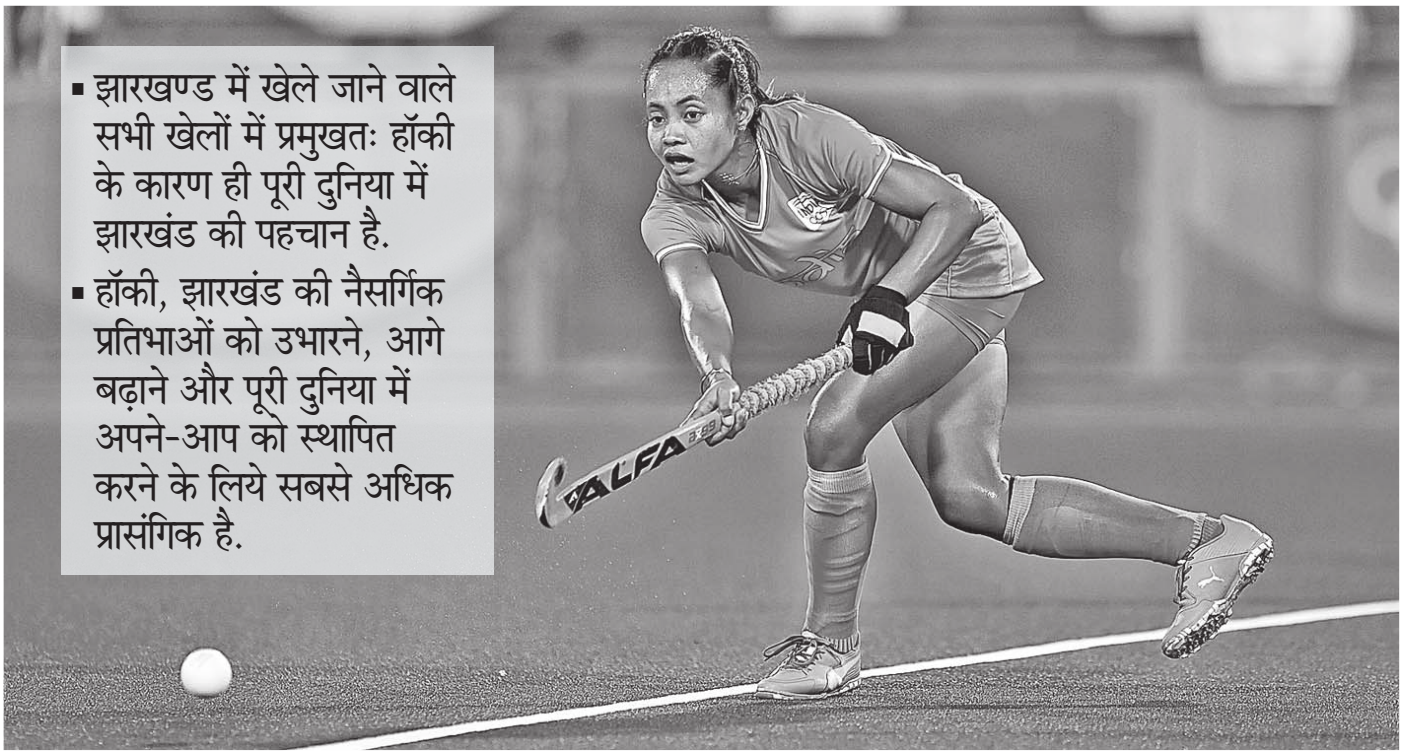

- झारखण्ड में खेले जाने वाले सभी खेलों में प्रमुखतः हॉकी के कारण ही पूरी दुनिया में झारखंड की पहचान है.
- हॉकी, झारखंड की नैसर्गिक प्रतिभाओं को उभारने, आगे बढ़ाने और पूरी दुनिया में अपने-आप को स्थापित करने के लिये सबसे अधिक प्रासंगिक है.

▪ चंचल भट्टाचार्य

रांची में आयोजित पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग अपेक्षा से कहीं अधिक उपलब्धियों से भरा रहा. भारतीय हॉकी को पूरे प्रोफेशनलिज्म अंदाज़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मजबूत, सशक्त, लड़ाकू और जिताऊ टीम बनाने की दिशा में यह ऐसा मजबूत प्रयास था जो न केवल पूरी तरह से कामयाब रहा बल्कि इसे लम्बे समय तक याद भी रखा जायेगा.

महिला युवा खिलाड़ियों को निखारने और उन्हें देश के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ खेलकर अपना खेल विकसित करने का अवसर प्रदान करने की दिशा में यह हॉकी इंडिया का एक महत्वपूर्ण कदम था. साथ ही यह चयनकर्ताओं के लिये राष्ट्रीय टीम के लिये युवा संभावनाओं की पहचान करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर बना.

झारखण्ड के परिप्रेक्ष्य में विशेष बात यह रही कि राज्य में हॉकी का गढ़ और भी मजबूत बना. पहली बार आयोजित इस राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग से न केवल झारखण्ड बल्कि देश में महिला हॉकी सुदृढ़ हुई साथ ही ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रेरणा भी मिली.

चाहे बात मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के समय की हो या फिर आज की लेकिन एक बात सामान्य है जो दोनों ही स्थितियों में समान रूप से लागू होती है. तब भी झारखण्ड हॉकी का गढ़ था और आज भी हॉकी का गढ़ है और यदि सटीक आकलन किया जाये तो आने वाले बरसों-बरस तक झारखंड की हॉकी की बादशाहत बरकरार रहेगी.

झारखण्ड में खेले जाने वाले सभी खेलों में प्रमुखतः हॉकी के कारण ही पूरी दुनिया में झारखंड की पहचान है.

हॉकी, झारखंड की नैसर्गिक प्रतिभाओं को उभारने, आगे बढ़ाने और पूरी दुनिया में अपने-आप को स्थापित करने के लिये सबसे अधिक प्रासंगिक है.

चाहे बात रांची की हो या फिर सिमडेगा, खूंटी, गुमला आदि के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की लेकिन एस्ट्रो टर्फ़ स्टेडियम से बहुत पहले से झारखण्ड में हॉकी खेली जाती रही है और झारखण्ड में हॉकी तभी से अपनी जड़ जमाये है जब यहाँ आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव था. गरीबी में पलते झारखण्ड के नौनिहालों ने ऐसी कलाबाजी दिखायी कि वे झारखण्ड के गाँव-देहात से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं तक छा गये.

पहले के दौर में झारखंड, केवल पुरुष हॉकी के क्षेत्र में अपना परचम फहराता था. लेकिन बाद में महिला हॉकी के क्षेत्र में झारखंड की स्थिति बहुत मजबूत हो गयी. यहाँ तक कि ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेनेवाली भारतीय टीम में अनेक महिला खिलाड़ी झारखंड से ही होती हैं. यह श्रृंखला विशेष रूप से तब से और भी मजबूत हुई जब से हॉकी इंडिया ने नये प्रबंधन और अपनी प्रोफेशनल मानसिकता के साथ अपना विस्तार करना शुरू किया. इसका बहुत अधिक सकारात्मक फायदा यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों और देश भर के हॉकी केन्द्रों को हुआ है. भारत की प्रतिष्ठा हॉकी के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ी है. हॉकी इंडिया की सबसे खास बात यह भी रही कि इसने मूल रूप से हॉकी की नर्सरी झारखण्ड, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में अपने आधार को और भी मजबूत करने का प्रयास किया. आज उड़ीसा और झारखंड, दो ऐसे प्रदेश हैं जो भारतीय हॉकी के परचम को पूरी दुनिया में फहराने की कुबत रखते हैं.

कुछ महीने पहले राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था जिसमें 6 देश की महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया. रांची में पहली बार आयोजित इस टूर्नामेंट में हांगझोऊ एशियाई खेल के चैंपियन चीन और रजत

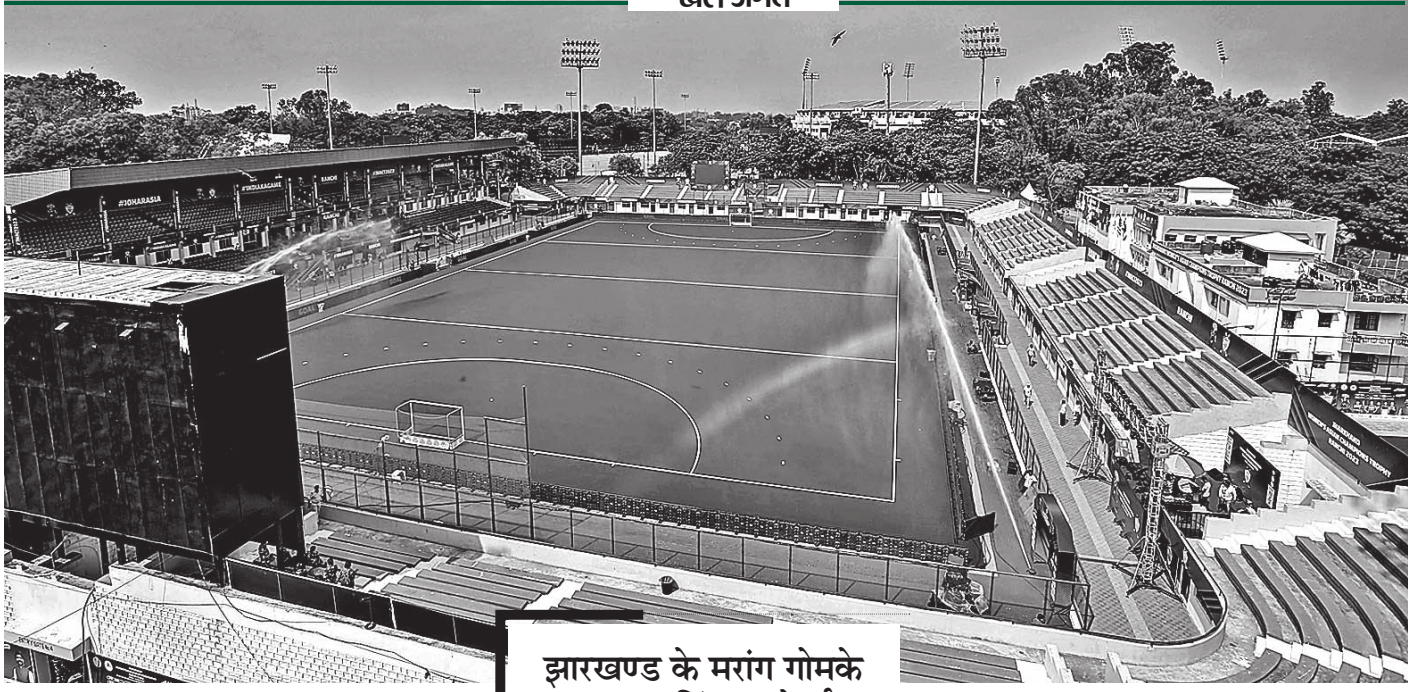

झारखण्ड के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम ने हाल ही में ओलंपिक क्वालीफायर और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के बाद एक और उपलब्धि को अपने खाते में दर्ज कर लिया.

पदक हंगरी के साथ ही मलेशिया, जापान और मेजबान भारत ने भाग लिया और सबसे दिलचस्प स्थिति यह रही कि भारतीय टीम न केवल चैंपियन बनी बल्कि सभी मुकाबले में वह अपराजेय रही और उसने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों को पराजित किया.

इसके तत्काल बाद झारखंड और रांची में ही भारत की मेजबानी में ओलंपिक क्वालीफायर मैच का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में अमेरिका, जर्मनी, जापान, चिली, चेक रिपब्लिक, इटली, न्यूजीलैंड के साथ ही शीर्ष वरीयता क्रम में दुनिया की छठे नंबर की टीम मेजबान भारतीय टीम ने भाग लिया. इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त तीन देशों ने पेरिस में 2024 में होनेवाली ओलंपिक में भाग लेने का टिकट पक्का किया. बहुत हद तक अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही और शीर्ष तीन स्थान में अपने-आपको कायम करने से चूक गयी.

अबकी बार फिर से एक महत्वपूर्ण मौका था हॉकी के राष्ट्रीय फलक पर रांची और झारखंड के छा जाने का. 30 अप्रैल से 9 मई 2024 तक भारत में महिलाओं के लिये राष्ट्रीय महिला घरेलू हॉकी लीग का आयोजन राजधानी रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में किया गया. पहली नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 की मेजबानी का मौका झारखंड को मिला जिसमें 14 वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2024 की शीर्ष आठ महत्वपूर्ण हॉकी टीम ने भाग लिया. हॉकी हरियाणा, हॉकी महाराष्ट्र, हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी बंगाल, हॉकी मिजोरम, मणिपुर हॉकी और हॉकी एसोसिएशन ऑफ़ ओडिशा के साथ ही मेजबान हॉकी झारखंड की टीम शामिल है. लीग मैचों के साथ ही क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में झारखंड के दर्शकों के साथ ही पूरे देश के हॉकी प्रेमियों को भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से रोमांचक हॉकी देखने का अवसर मिला.

वास्तव में यह मौका बहुत ही खास था और झारखंड और रांची के परिप्रेक्ष्य में इस अवसर को स्वर्णिम कहना कहीं अधिक बेहतर होगा. हॉकी के क्रेज को इस लीग के आयोजन से ज़बरदस्त बढ़ावा मिला. साथ ही यह हॉकी के संपूर्ण विकास और न जाने ऐसी कितनी बातों के लिये यह अभूतपूर्व मौका बना.

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह के अनुसार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कुल मिलाकर भारतीय हॉकी, विशेषकर महिला खिलाड़ियों के लिये एक महत्वपूर्ण क्षण बना. उन्होंने कहा कि यह लीग महिला खेलों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है और देश में महिला हॉकी की वृद्धि और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का शुभारंभ भारत में महिला खेलों के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है. यह लीग न केवल विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के लिए एक मंच प्रदान करने वाला रहा बल्कि युवा लड़कियों को हॉकी के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिये प्रेरित करने में भी सफल रहा.

झारखण्ड के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम ने हाल ही में ओलंपिक क्वालीफायर और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के बाद एक और उपलब्धि को अपने खाते में दर्ज कर लिया.

लीग चरण में प्रत्येक टीम ने तीन विश्राम दिवसों 2, 5 और 8 मई के साथ सात मैच खेला. राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 30 अप्रैल को शुरू हुई जिसमें शुरुआत में हरियाणा का मुकाबला ओडिशा टीम से हुआ. अंक संरचना के तहत सामान्य समय में खेल जीतने पर 3 अंक, ड्रा के बाद शूटआउट के विजेता को 1 अंक और 1 बोनस अंक अर्थात कुल दो अंक देने का प्रावधान था.

पहले दिन रोमांचक खेल देखने को मिला. हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी हरियाणा पर 4-1 से दबदबा बनाया जबकि हॉकी महाराष्ट्र ने मणिपुर हॉकी को 5-1 से आसानी से हरा दिया.

इस महिला हॉकी लीग में झारखण्ड को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. 10 दिन के आखिरी मैच में झारखंड को रोमांचक मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाफ सदन डेथ में हार का सामना करना पड़ा. झारखण्ड 15 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा वहीं 16 अंक के साथ हरियाणा की टीम पहले स्थान पर रही. ओडिशा की टीम ने 7 मैच में 15 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. गोल के अंतर के कारण झारखंड को दूसरा स्थान मिला. झारखण्ड ने कुल 7 मैच में 15 गोल किये वहीं ओडिशा ने 7 मैच में छह गोल किये. शीर्ष पर रही हरियाणा की टीम ने सात मैच में 8 गोल मारते हुए सबसे अधिक अंक प्राप्त किया. लीग की अन्य टीमों में मध्य प्रदेश चतुर्थ, महाराष्ट्र पाँचवें, पश्चिम बंगाल छठे, मिजोरम सातवें और मणिपुर की टीम आठवें स्थान पर रही.

दूसरे चरण का मुकाबला अक्टूबर में खेला जाएगा जिसके बाद चैंपियन का फैसला होगा.

भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे और उन्होंने सभी आठ टीम की खिलाड़ियों से बातचीत की. इस लीग के दौरान हॉकी इंडिया के अधिकारी, जिनमें हाई-परफार्मेंस निदेशक हरमन क्रूज़, वरिष्ठ महिला मुख्य कोच हरेंद्र सिंह और जूनियर महिला कोच तुषार खांडकर आदि भी उपस्थित हुए.

कुल मिलाकर राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग भारतीय महिला घरेलू हॉकी संरचना के लिये एक महत्वपूर्ण क्षण बना. यह विशिष्ट प्रतियोगिता हमारे शीर्ष घरेलू खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने कौशल को और निखारने के लिये माध्यम बना. विश्वास है कि यह लीग न केवल घरेलू हॉकी के स्तर को ऊपर उठायेगी बल्कि राष्ट्रीय टीम के लिये भविष्य के सितारों की पहचान, तैयारी और पोषण के लिये एक मजबूत आधार का काम करेगी.

राशिफल

मेष मेष राशि के लिए जून के महीने की शुरुआत में कुछ समस्याओं के साथ होगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उनका बहुत हद तक समाधान निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इष्ट-मित्रों की मदद से अटके हुए कार्यों में गति आएगी। इस दौरान करिअर-कारोबार में प्रगति के लिए अत्यधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है।

मिथुन मिथुन राशि को जून महीने में समय,धन और ऊर्जा का सही प्रबंधन करके चलने की जरूरत रहेगी। जून माह की शुरुआत में घर की जरूरतों अथवा सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर जेब से ज्यादा धन खर्च हो सकता है,जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर अपने सूझबूझ से उन्हें दूर करने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे।

सिंह सिंह राशि के लिए जून का महीना शुभता और सौभाग्य को साथ लिए है। इस माह आपको कदम-कदम पर सफलता और इष्ट-मित्रों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। जून माह की शुरुआत में ही आपको समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। घर-परिवार के लोग आपके द्वारा लिए गए फैसले की प्रशंसा करेंगे।

तुला तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिलाजुला साबित होने जा रहा है। माह की शुरुआत में आपको घर-परिवार और कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा,जिससे आप सही समय पर बेहतर निर्णय ले पाएंगे और अपना बेहतर आउटपुट देने में कामयाब होंगे। यह समय परीक्षा-प्रतियोगिता में जुटे लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा।

धनु धनु राशि के जातकों के लिए जून माह की शुरुआत शुभता और सौभाग्य लिए होगी। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त रहेगा। जिसकी मदद से आप अपना बेहतर आउटपुट दे पाएंगे और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यदि आप लंबे समय से करिअर और कारोबार को लेकर प्रयासरत थे,तो आपको इस दौरान मनचाही सफलता प्राप्त होगी।

कुंभ कुंभ राशि के लिए को जून माह में बेहद सावधानी और समझदारी के साथ कोई कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। माह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्य समय पर न पूरे हो पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रह सकता है,लेकिन आपको कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं बल्कि 'हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम' का मंत्र हमेशा याद रखना है।

वृषभ वृष राशि के लिए जून माह की शुरुआत कार्यक्षेत्र की कुछ उलझनों और घर-परिवार की कुछ समस्याओं से होगी। इस दौरान आपको अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन करना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ चीजों को लेकर विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी कुछ अड़चनें आ सकती है।

कर्क कर्क राशि के जातकों के लिए जून के महीने की शुरुआत मिलीजुली साबित होगी। इस दौरान जहां आपको अपने करिअर और कारोबार को आगे बढ़ाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे,वहीं आपकी सेहत उसमें ब्रेकर का काम करेगी। ऐसे में आपको अपने कामकाज के साथ अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वाहन सावधानी के साथ चलाएं अन्यथा चोट-चपेट के शिकार भी हो सकते हैं।

कन्या कन्या राशि के लिए को जून के महीने में अपने सेहत,संबंध और कामकाज को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। किसी भी कार्य को दूसरे के भरोसे छोड़ने या उस पर आश्रित रहने की बजाय स्वयं करने की कोशिश करें,अन्यथा उसमें आपको नुकसान हो सकता है। विशेष रूप से यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको धन संबंधी चीजों को क्लीयर करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। किसी

वृश्चिक वृश्चिक राशि के लिए जून माह की शुरूआत करिअर की दृष्टि से शुभ तो वहीं सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ी चिंताजनक कही जाएगी। माह की शुरुआत में आपको आपको अपने करिअर और कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे लेकिन इस दौरान आपकी सेहत और आपके साथी आपको धोखा दे सकते हैं। माह के मध्य में व्यवसाय से जुड़े फैसले सोच-कर लें,अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है।

मकर मकर राशि के लिए जून का महीना बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। माह की शुरुआत में आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस दौरान आप किसी के बहकावे में आकर किसी योजना में अपना धन न लगाएं अन्यथा आपका धन फंस सकता है। साथ ही साथ इस दौरान आपको फालतू की चीजों में फसने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की जरूरत रहेगी।

मीन मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिला-जुला साबित होने वाला है। माह की शुरुआत घर-परिवार के सदस्य से जुड़ी शुभ सूचना से होगी,जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान इष्ट-मित्रों की से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। जून माह के दूसरे सप्ताह में आपको अपने कामकाज,सेहत और संबंधों को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत रहेगी।

कार्तिक के मामा-मामी की मौत घाटकोपर होर्डिंग हादसे में गई जान

13 मई को हुए मुंबई में घाटकोपर होर्डिंग हादसे में कार्तिक आर्यन के मामा-मामी की मौत हो गई है। इंदौर एयरपोर्ट के पूर्व डायरेक्टर मनोज चंसोरिया और उनकी वाइफ अनीता चंसोरिया जबलपुर के सिविल लाइन में स्थित मरियम चौक में रहते थे। हादसे के लगभग 56 घंटे के बाद दोनों की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। इस मामले में रिश्तेदारों का कहना है कि दोनों अपनी कार से मुंबई से इंदौर के रास्ते जबलपुर वापस लौटने वाले थे, तभी करीब 4:30 बजे वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पंत नगर में एक पेट्रोल पंप में कार में पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे। तभी तूफान आ गया और उनकी कार होर्डिंग की चपेट में आ गई। अगर वो पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं रूकते तो शायद एक्टर के मामा-मामी की जान बच जाती।

कार्तिक आर्यन के दिवंगत मामा मनोज चंसोरिया इंदौर एयरपोर्ट के पूर्व डायरेक्टर थे। वह अपनी पत्नी अनिता चंसोरिया के साथ जबलपुर के सविलि लाइंस स्थति मरियम चौक इलाके में रहते थे। बताया जाता है कि दोनों कार से मुंबई गए थे और सोमवार को वापस जबलपुर लौट रहे थे। इसी दौरान कार में तेल डलवाने के लिए वह पेट्रोल पंप पर रुके थे। तभी अचानक आए आंधी-तूफान ने उन्हें घेर लिया।

कांस का हिस्सा बनीं कियारा आडवाणी

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी कांस इवेंट में शामिल हुईं। उन्होंने अपने कांस डेब्यू के लिए व्हाइट हाई स्लिट गाउन चुना, जिसमें वे बेहद खूबसूरत दिखीं। कियारा ने इस लुक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वहीं, ऐश्वर्या राय का दूसरा लुक सामने आया। कांस में दूसरे दिन ऐश्वर्या को पेस्टल पिंक और ग्रीन गाउन में देखा गया। एक्ट्रेस 22 साल से कांस का हिस्सा बनती आ रही हैं। इस बार उनका हाथ भी फ्रैक्चर है। इसके बावजूद उन्होंने ये इवेंट अटेंड किया। इस इवेंट में ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ पहुंची हैं। दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आराध्या उन्हें सहारा देती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि ऐश्वर्या के हाथ में चोट लगी है। मां को इस तरह सपोर्ट करते देख यूजर्स आराध्या की तारीफ कर रहे हैं।

नायक का बनेगा सीक्वल, प्रोड्यूसर ने दी हिंट, 2001 में रिलीज हुआ था फर्स्ट पार्ट

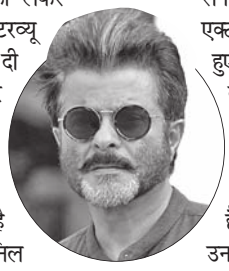

नायक के सीक्वल बनाने को लेकर प्रोड्यूसर मुकुट ने हालिया इंटरव्यू में इस बात पर मुहर लगा दी है कि फिल्म के सीक्वल पर काम जारी है। मेकर्स जल्द ही अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि पिछली बार की तरह अनिल कपूर और रानी मुखर्जी की जोड़ी देखने को मिल सकती है। प्रोड्यूसर मुकुट ने एक इंटरव्यू में बताया, 'हम सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत समय पहले ही प्रोड्यूसर एएम रत्नम से फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे। हम सभी लीड एक्टर्स और अन्य कलाकारों को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे ही राइटिंग का काम पूरा हो जाएगा, हम आगे की प्लानिंग करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा, इस पर विचार किया जा रहा है। 1-2 डायरेक्टर नजर में हैं, लेकिन किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है।' मुकुट ने यह भी बताया कि फिल्म को लेकर उनकी बातचीत अनिल कपूर और रानी मुखर्जी से जारी है। नए किरदार कौन होंगे, इस पर भी अभी कोई प्लानिंग नहीं की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरे पार्ट में कहानी वहां से शुरू होगी, जहां पिछले पार्ट में खत्म हुई थी।

संसद भवन की दहलीज लांघने झारखंड में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी 5 महिलाएं

गीता, अन्नपूर्ण दूसरी बार आजमा रही हैं भाग्य, कल्पना भी विस में जाने को है आतुर

▪ सत्येन्द्र, रांची

झारखंड में मिशन 2024 का मुकबला बड़ा ही रोचक हो गया है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच झारखंड के 14 सीटो पर हो रहे मुकाबले में देनो ही गठबंधन ने पांच महिला उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया है। चुनावी समर में उतरी महिला उम्मीदवारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार संसद भवन में दहलीज पर कदम रखने के लिए चुनावी मैदान में आमने-सामने की जोर आजमाइश कर रही है। इनमें से दो महिला प्रत्याशी क्रमशः अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा वर्तमान में सांसद हैं। वे दूसरी बार चुनाव में खड़ी हैं। इन महिला प्रत्याशियों में ज्यादातर का जुड़ाव राजनीतिक परिवार या विरासत से है। अन्य महिला प्रत्याशियों में कांग्रेस से यशस्विनी सहाय, जोबा मांझी, अनुपमा सिंह, सीता सोरेन, ममता भुइयां शामिल हैं। जबकि गांडेय विस उपचुनाव में झामुमो से कल्पना सोरेन ने ताल ठोंका है। लोकसभा चुनाव 2024 न सिर्फ उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने का मौका दे रही है, बल्कि किसी को अपने पिता तो किसी को अपने पति की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की भी यह लड़ाई है।

गीता कोड़ा : सिंहभूम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वर्तमान सांसद गीता कोड़ा मैदान में हैं। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनीं गीता कोड़ा की पहचान उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से है। भ्रष्टाचार के मामले में जब मधु कोड़ा फंसते चले गए तब उनकी राजनीतिक विरासत को गीता कोड़ा ने बखूबी आगे बढ़ाया। गीता कोड़ा विधायक और सांसद बन कर राजनीति में हमेशा सक्रिय रहीं है। फिलहाल देश का चौथा और झारखंड के पहले चरण के चुनाव यानी 13 मई को उनका किस्मत ईवीएम में कैद हो गया है। अब इनका किस्मत का पिटारा चार जून को खुलेगा।

सीता सोरेन : दुमका लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में इस बार सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड के सबसे बड़े राजनीति घराने शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन का पदार्पण राजनीति में तब हुआ जब उनके पति दुर्गा सोरेन की आकस्मिक निधन 2009 में हो गया था। अपने पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सीता सोरेन झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल होकर लोकसभा उम्मीदवार बनीं हैं।

अनुपमा सिंह : धनबाद लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने पहली बार अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की पत्नी और राज्य के कद्दावर मजदूर नेता और मंत्री रहे राजेंद्र सिंह की बहू के रूप में अनुपमा सिंह की पहचान है। अब उनके ऊपर अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही है।

जोबा मांझी : सिंहभूम लोकसभा सीट से इस बार इंडिया गठबंधन से झामुमो ने जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जोबा मांझी की गिनती आज की तारीख में धुरंधर राजनीतिज्ञ में होती है। पांच बार विधायक और कई बार बिहार और झारखंड में मंत्री रह चुकी जोबा मांझी का भी राजनीति में प्रवेश तब हुआ था जब उनके पति देवेंद्र मांझी की हत्या कर दी गयी थी। अब लोकसभा उम्मीदवार के रूप में पति की राजनीतिक विरासत को एक कदम और आगे बढ़ाने की लड़ाई जोबा मांझी लड़ रही हैं। जोबा माझी का भी किस्मत झारखंड के पहले चरण के चुनाव में ईवीएम में कैद हो गया है। इनका मुख्य मुकाबला ईजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ था।

यशश्विनी सहाय : रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय की भी झारखंड की राजनीति में एंट्री उनके राजनीतिक विरासत की वजह से ही हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय, पेशे से मुंबई में अधिवक्ता रही हैं और वह राजनीति से दूर रहती थीं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तब अपने पिता सुबोधकांत सहाय की राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है।

ममता भुइयां: पलामू से इस बार राजद की ओर से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार ममता भुइयां को बनाया गया है। राजनीति में पहली बार प्रवेश करने वाली ममता भुइयां की पहचान पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां से जुड़ा है। ममता भुइयां, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के भाई की पत्नी हैं। अब उन पर अपने परिवार की सियासी विरासत बढ़ाने और खुद को राजनीति में प्रतिष्ठित करने की चुनौती है। ममता भुइयां की भी किसमत फिलहाल ईवीएम में बंद हो चुका है।

अन्नपूर्णा देवी : कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में इस बार भी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी चुनाव मैदान में हैं। अन्नपूर्णा देवी की राजनीति में प्रवेश उनके पति और संयुक्त बिहार में मंत्री रहे रमेश प्रसाद यादव की असामयिक निधन के बाद हुआ था। वह राजनीति में न बेहद सक्रिय रही हैं बल्कि सफल भी रही।

कल्पना सोरेन : लोकसभा के साथ साथ इस बार गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में हैं। जब ईडी की कार्रवाई में पति हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया तो कल्पना सोरेन घर की दहलीज से बाहर निकलीं बल्कि गांडेय उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार हैं। उनके ऊपर भी संकट की इस घड़ी में परिवार और पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है।

अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, वीडी राम एवं समीर उराँव का किस्मत ईवीएम में बंद

झारखंड के पहले चरण का चुनाव त 13 मई को संपन्न हो गया। इस चरण में राज्य की चार महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुआ। झारखंड के हिसाब से यहां के पहले चरण में सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू में मतदान हुआ। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि क्या इन सीटों पर (सिंहभूम छोड़कर) 2019 की तरह भाजपा फिर से अपनी जीत का झंडा लहरा सकेगी। खूंटी से अर्जुन मुंडा, पलामू से वीडी राम, लोहरदगा से समीर उराँव और गीता कोड़ा (अब भाजपा) सिंहभूम सीट से जीत हासिल कर सकेंगे। इंडी अलायंस की ओर से खूंटी सीट पर कालीचरण मुंडा (पूर्व विधायक), पलामू से ममता भुइयां, लोहरदगा से सुखदेव भगत (पूर्व विधायक) और सिंहभूम से जोबा मांझी (पूर्व मंत्री) मैदान में है। चुनाव संपन्न होने के बाद 4 जून को मतगणना के दिन किसका किस्मत रंग लाएगी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है।

Postal Registration No. : RN/262/2023 25

रांची में शाह ने रोड शो किया:भगवा रंग की गाड़ी से निकले, छतों से बरसे फूल; जय श्री राम के नारे लगे

दो किलोमीटर लंबा गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो करीब सवा घंटा में पूरा हुआ। इसमें लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जमकर श्रीराम और भारत माता के जयकारे लगाये। चुटिया के इंदिरा गांधी चौक से शाम 5.28 बजे रोड शो शुरू हुआ। आलम यह रहा कि सड़क के दोनों और खचाखच भीड़ थी और लोग हाथों में भाजपा के झंडे और नरेंद्र मोदी का कट आउट लिये हुए थे। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में आयोजित रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता का अभिवादन कर भाजपा प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगा। वह लोगों पर पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उपस्थित भीड़ पर फूल बरसा रही थी। रोड शो के दौरान स्वागत के लिए यात्रा मार्ग की दोनों ओर की सड़क भगवामय हो गयी।

झंडा और पीएम का मुखौटा लगाये दिखे कार्यकर्ता: हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा और मोदी का मुखौटा लगाकर जयकारे लगाते रहे। रोड शो को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। इससे पहले रोड शो जैसे ही शुरू हुआ, विजयी भवः भाजपा लिखा एक पोस्टर लेकर महिला पर अमित शाह की नजर पड़ी। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, तो महिला ने प्रणाम किया। अमित शाह का रोड शो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। जगह-जगह मंत्रोच्चार और शंखनाद हो रहा था।

हाथ में कमल चुनाव चिन्ह

अमित शाह के रथ पर सांसद सह रांची के प्रत्याशी संजय सेठ भी थे। उनके हाथ कमल फूल का चुनाव चिह्न है। लोग प्रभु श्रीराम के जयकारे लगा रहे थे। इधर, माइक से गाना भी बज रहा था कि जो राम को लाये हैं, उनको हम लायेंगे...। साथ ही झारखंडी गीत-संगीत से सराबोर रोड शो का अदभुत नजारा दिखा। पुलिस भी सड़क के अलावा छतों पर भी तैनात दिखी। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम था।